RNI No. GUJHIN/2011/39228

गरवी गुजरात

GARVI GUJARAT

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 15
अंक : 287
दि. 18.02.2026,
बुधवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

बदलाव की दहलीज पर बांग्लादेश: तारिक रहमान के नेतृत्व में नए राजनीतिक युग की शुरुआत

(जीएनएस)। दक्षिण एशिया के राजनीतिक परिदृश्य में एक ऐतिहासिक मोड़ उस समय आया जब तारिक रहमान ने पड़ोसी देश बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेकर एक नए राजनीतिक अध्याय की शुरुआत की। यह केवल सत्ता परिवर्तन नहीं है, बल्कि एक लंबे समय से चले आ रहे राजनीतिक वर्चस्व के अंत और नए नेतृत्व की स्थापना का संकेत भी है। राजधानी ढाका के प्रतिष्ठित जातीय संसद भवन परिसर में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह ने न केवल देश बल्कि पूरे दक्षिण एशिया का ध्यान आकर्षित किया। इस समारोह में देश के राजनीतिक, सामाजिक और अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों की मौजूदगी ने इस क्षण को और अधिक महत्वपूर्ण बना दिया।

तारिक रहमान का प्रधानमंत्री बनना इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि पिछले लगभग तीन दशकों से बांग्लादेश की राजनीति पर दो प्रमुख महिला नेताओं का वर्चस्व रहा था। इनमें प्रमुख थीं शेख हसीना और खालिदा जिया, जिन्हें अक्सर बांग्लादेश की राजनीति की "दो बेगमों" के रूप में जाना जाता था। इन दोनों नेताओं ने अलग-अलग समय पर देश का नेतृत्व किया और देश की नीतियों और दिशा को निर्धारित किया। ऐसे में तारिक रहमान का सत्ता में आना केवल नेतृत्व परिवर्तन नहीं बल्कि एक नई राजनीतिक पीढ़ी के उदय का प्रतीक माना जा रहा है।

तारिक रहमान की वापसी अपने आप में एक संघर्ष और धैर्य की कहानी है। लगभग 17 वर्षों तक देश से बाहर रहने के बाद उनका वापस आना और फिर लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से प्रधानमंत्री बनना उनके राजनीतिक जीवन की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। वे पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान के पुत्र हैं और उनकी राजनीतिक विरासत ने उन्हें देश की राजनीति में एक मजबूत आधार प्रदान किया। लेकिन केवल विरासत के बल पर सत्ता प्राप्त करना संभव नहीं होता, इसके लिए जनसमर्थन, संगठनात्मक क्षमता और दूरदृष्टि भी आवश्यक होती है, जो तारिक रहमान ने अपने नेतृत्व में प्रदर्शित की।

12 फरवरी को हुए आम चुनावों में उनकी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने शानदार जीत हासिल की। 300 सदस्यीय संसद में पार्टी ने 151 से अधिक सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया। गठबंधन के साथ मिलकर यह संख्या 212 तक पहुंच गई, जिसने उनकी सरकार को स्थिरता और मजबूती प्रदान की। यह जनादेश केवल एक राजनीतिक जीत नहीं बल्कि जनता की अपेक्षाओं और विश्वास का प्रतीक भी है।

शपथ ग्रहण समारोह में बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने तारिक रहमान को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर उन्होंने देश के संविधान की रक्षा करने और जनता की सेवा

करने का संकल्प लिया। यह शपथ केवल एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं बल्कि देश के प्रति जिम्मेदारी और समर्पण का प्रतीक है। तारिक रहमान की नई कैबिनेट में 25 मंत्रियों और 24 राज्य मंत्रियों को शामिल किया गया है। इस कैबिनेट में अनुभवी नेताओं के साथ-साथ नए और युवा चेहरों को भी स्थान दिया गया है, जिससे सरकार में संतुलन और नवीनता दोनों सुनिश्चित हो सके। विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदायों को प्रतिनिधित्व देकर उन्होंने समावेशी शासन का संदेश दिया है। हिंदू और बौद्ध समुदाय के प्रतिनिधियों को शामिल करना यह दर्शाता है कि उनकी सरकार सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की प्रतिबद्धता रखती है। भारत और बांग्लादेश के संबंधों की दृष्टि से भी यह परिवर्तन महत्वपूर्ण है। भारत की ओर से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ढाका जाकर तारिक रहमान से मुलाकात की और उन्हें प्रधानमंत्री बनने की बधाई दी। इस दौरान उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भेजा गया संदेश भी उन्हें सौंपा। यह मुलाकात दोनों देशों के बीच मजबूत और सहयोगपूर्ण संबंधों की निरंतरता का संकेत है। भारत और बांग्लादेश के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध रहे हैं, और नए नेतृत्व से इन संबंधों को और मजबूत करने की उम्मीद जताई जा रही है।

तारिक रहमान के सामने कई महत्वपूर्ण चुनौतियां भी हैं। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, बेरोजगारी को कम करना, कानून-व्यवस्था को सुधारना और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बांग्लादेश की स्थिति को सुदृढ़ करना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है। इसके अलावा संवैधानिक सुधार और प्रशासनिक पारदर्शिता सुनिश्चित करना भी उनके एजेंडे का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

आर्थिक मोर्चे पर बांग्लादेश ने पिछले वर्षों में उल्लेखनीय प्रगति की है, लेकिन वैश्विक आर्थिक अस्थिरता और आंतरिक चुनौतियों के कारण विकास की गति प्रभावित हुई है। ऐसे में तारिक रहमान की सरकार को निवेश को बढ़ावा देने, उद्योगों को प्रोत्साहित करने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने पर विशेष ध्यान देना होगा। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों जैसे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ सहयोग और आर्थिक सुधारों के माध्यम से वे देश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे सकते हैं।

राजनीतिक दृष्टि से भी यह समय बांग्लादेश के लिए महत्वपूर्ण है। लंबे समय तक एक ही प्रकार के नेतृत्व के बाद जनता अब बदलाव और नई सोच की अपेक्षा कर रही है। तारिक रहमान के नेतृत्व में सरकार को जनता के विश्वास पर खरा उतरना होगा और यह साबित करना होगा कि वे केवल सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन लाने में सक्षम हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इस परिवर्तन को ध्यान से देखा जा रहा है। दक्षिण एशिया में राजनीतिक स्थिरता और सहयोग क्षेत्रीय शांति और विकास के लिए आवश्यक है। बांग्लादेश का नया नेतृत्व क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अपनी भूमिका को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा सकता है।

तारिक रहमान का प्रधानमंत्री बनना केवल एक व्यक्ति की सफलता नहीं बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया की जीत है। यह इस बात का प्रमाण है कि लोकतंत्र में जनता की इच्छा सर्वोपरि होती है और वही अंततः देश की दिशा निर्धारित करती है। उनकी सरकार के सामने अवसर भी हैं और चुनौतियां भी, लेकिन यदि वे पारदर्शिता, ईमानदारी और दूरदृष्टि के साथ कार्य करते हैं, तो वे बांग्लादेश को एक नए युग की ओर ले जा सकते हैं।

आज बांग्लादेश एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां अतीत की विरासत और भविष्य की संभावनाएं एक साथ मौजूद हैं। तारिक रहमान का नेतृत्व इस बात पर निर्भर करेगा कि वे इन दोनों के बीच संतुलन कैसे स्थापित करते हैं। यदि वे जनता की अपेक्षाओं पर खरे उतरते हैं और देश को स्थिरता, विकास और समावेशिता की दिशा में आगे बढ़ाते हैं, तो उनका कार्यकाल बांग्लादेश के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में दर्ज किया जाएगा।

इस ऐतिहासिक परिवर्तन ने न केवल बांग्लादेश की राजनीति को नई दिशा दी है, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के लिए भी एक संदेश दिया है कि लोकतंत्र में बदलाव संभव है और जनता की शक्ति सबसे बड़ी होती है। आने वाले वर्षों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि तारिक रहमान का नेतृत्व किस प्रकार देश के भविष्य को आकार देता है और बांग्लादेश को एक मजबूत, समृद्ध और स्थिर राष्ट्र बनाने में कितनी सफलता प्राप्त करता है।

मोटापा बना संक्रमण का छिपा हुआ खतरा रिसर्च में सामने आया चौंकाने वाला सच

(जीएनएस)। लंदन। आधुनिक जीवनशैली में तेजी से बढ़ता मोटापा अब केवल शरीर की बनावट या दिखावट का मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि यह जीवन और मृत्यु के बीच का निर्णायक कारक बनता जा रहा है। हाल ही में ब्रिटेन और फिनलैंड के स्वास्थ्य विशेषज्ञों द्वारा किए गए एक व्यापक अध्ययन में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि दुनिया भर में संक्रमण से होने वाली हर दस में से एक मौत मोटापे से जुड़ी होती है। यह अध्ययन करीब 5.4 लाख लोगों पर किया गया, जिसमें यह पाया गया कि जिन लोगों का वजन सामान्य से अधिक होता है, उन्हें संक्रमण के कारण अस्पताल में भर्ती होने और जान गंवाने का खतरा कई गुना अधिक रहता है। शोध में सामने आया कि मोटापे का शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता पर गहरा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सामान्य वजन वाले व्यक्ति की तुलना में मोटापे से ग्रस्त व्यक्ति को गंभीर संक्रमण होने का खतरा लगभग 70 प्रतिशत अधिक होता है। स्थिति तब और गंभीर हो

जाती है, जब किसी व्यक्ति का बॉडी मास इंडेक्स (बीएमआई) 40 से ऊपर पहुंच जाता है, जिसे अत्यधिक मोटापे की श्रेणी में रखा जाता है। ऐसे लोगों में संक्रमण के कारण मृत्यु का खतरा तीन गुना तक बढ़ जाता है। यह खतरा केवल कोविड-19 या फ्लू जैसे चर्चित संक्रमणों तक सीमित नहीं है, बल्कि निमोनिया, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, पेट से जुड़े संक्रमण और सांस संबंधी बीमारियों में भी मोटापा गंभीर जटिलताएं पैदा करता है। विशेषज्ञों का कहना है कि मोटापे के कारण शरीर में अतिरिक्त वसा जमा हो जाती है, जो धीरे-धीरे शरीर के आंतरिक तंत्र को प्रभावित करती है। यह अतिरिक्त चर्बी शरीर में सूजन (इन्फ्लेमेशन) को बढ़ाती है और इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देती है। जब रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है, तब शरीर संक्रमण से प्रभावी ढंग से लड़ नहीं पाता और बीमारी तेजी से गंभीर रूप ले लेती है। यही कारण है कि मोटे लोगों को संक्रमण होने पर उनकी स्थिति सामान्य व्यक्ति की तुलना में जल्दी बिगड़ सकती है। शोधकर्ताओं ने यह भी बताया कि मोटापे का असर केवल संक्रमण के जोखिम तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह संक्रमण से उबरने की क्षमता को भी प्रभावित करता है। मोटे लोगों में संक्रमण के बाद रिकवरी की प्रक्रिया धीमी होती है और जटिलताएं अधिक देखने को मिलती हैं। अस्पताल में भर्ती होने की संभावना भी अधिक होती है, जिससे स्वास्थ्य प्रणाली पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। हालांकि इस अध्ययन में एक सकारात्मक पहलू भी सामने आया है। विशेषज्ञों के अनुसार, यदि व्यक्ति समय रहते अपना वजन नियंत्रित कर ले, तो संक्रमण से गंभीर रूप से प्रभावित होने का खतरा लगभग 20 प्रतिशत तक कम किया जा सकता है। इसका अर्थ यह है कि जीवनशैली में छोटे-छोटे बदलाव भी व्यक्ति के जीवन को सुरक्षित बना सकते हैं। संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद और तनाव नियंत्रण जैसे उपाय मोटापे को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि मोटापा एक "साइलेंट रिस्क फैक्टर" बन चुका है, जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। लोग इसे केवल सौंदर्य या आत्मविश्वास से जोड़कर देखते हैं, जबकि यह शरीर के अंदर कई गंभीर बीमारियों की जड़ बन सकता है। मोटापा न केवल संक्रमण, बल्कि हृदय रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप और कैंसर जैसी बीमारियों के खतरे को भी बढ़ाता है।

चाय बागान जनजातियों को सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम, हिमंता सरकार ने खोले नए अवसर

(जीएनएस)। नई दिल्ली। पूर्वोत्तर भारत के सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए असम की असम सरकार ने सरकारी नौकरियों में चाय बागान जनजातियों और आदिवासी समुदायों के लिए तीन प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी देकर एक बड़ा कदम उठाया है। यह फैसला राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने की। इस निर्णय को राज्य के सबसे वंचित और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए सामाजिक न्याय और समान अवसर सुनिश्चित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल माना जा रहा है।

सरकार के इस फैसले के तहत अब चाय बागान जनजातियों और आदिवासी समुदायों को प्रथम और द्वितीय श्रेणी की सरकारी नौकरियों में भी आरक्षण का लाभ मिलेगा। अब तक इन समुदायों को केवल तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों में आरक्षण प्राप्त था, जिससे उनकी भागीदारी निचले स्तर तक सीमित रह जाती थी। नए निर्णय के बाद अब इन समुदायों के युवाओं को उच्च प्रशासनिक और नीति-निर्माण से जुड़े पदों तक पहुंचने का अवसर मिलेगा, जिससे उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में व्यापक सुधार होने की उम्मीद है।

मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने इस फैसले को सामाजिक समानता और समावेशी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि चाय बागान जनजातियां और आदिवासी समुदाय असम की अर्थव्यवस्था की रीढ़ रहे हैं, विशेषकर चाय उद्योग में उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। इसके बावजूद, वर्षों से इन समुदायों का प्रतिनिधित्व उच्च सरकारी पदों पर बेहद सीमित रहा है। सरकार का यह निर्णय इस ऐतिहासिक असमानता को दूर करने और इन समुदायों को सम्मानजनक अवसर प्रदान करने की दिशा में एक ठोस प्रयास है।

असम भारत का सबसे प्रमुख चाय उत्पादक राज्य है और यहां के चाय बागानों में काम करने वाले श्रमिकों का एक बड़ा हिस्सा जनजातीय और आदिवासी समुदायों से आता है। इन समुदायों ने पीढ़ियों से कठिन परिस्थितियों में काम करते हुए राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में वे लंबे समय तक पिछड़े रहे, जिसके कारण उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति अपेक्षाकृत कमजोर बनी रही।

सरकार का मानना है कि आरक्षण का यह विस्तार इन समुदायों के युवाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगा और उन्हें प्रशासनिक सेवाओं में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। इससे न केवल इन युवाओं के जीवन स्तर में सुधार होगा, बल्कि शासन व्यवस्था में भी विविधता और संतुलन आएगा। जब समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व प्रशासन में होता है, तो नीतियां अधिक समावेशी और प्रभावी बनती हैं।

इस फैसले का राजनीतिक महत्व भी कम नहीं है। आगामी चुनावों को देखते हुए इसे सरकार की एक रणनीतिक पहल के रूप में भी देखा जा रहा है। चाय बागान जनजातियां और आदिवासी समुदाय असम की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मतदाता वर्ग हैं और उनका समर्थन चुनावी परिणामों को प्रभावित करने में अहम भूमिका निभाता है। ऐसे में सरकार का यह कदम इन समुदायों के बीच विश्वास और समर्थन को मजबूत करने का प्रयास माना जा रहा है। हालांकि, सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय केवल राजनीतिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और समान अवसर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार राज्य के हर वर्ग के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और किसी भी समुदाय को पीछे नहीं छोड़ना चाहती।

नाबालिग से दरिंदगी का कठोर परिणाम: सूरत पॉक्सो मामले में किशोर दोषी को 20 साल की सजा, 21 वर्ष पूरा होते ही भेजा जाएगा जेल

(जीएनएस)। सूरत शहर में दर्ज एक गंभीर और संवेदनशील पॉक्सो मामले में किशोर न्यायालय द्वारा सुनाया गया फैसला न केवल न्याय व्यवस्था की दृढ़ता को दर्शाता है, बल्कि समाज को भी एक स्पष्ट संदेश देता है कि जघन्य अपराध करने वालों को उम्र की आड़ में छूट नहीं मिल सकती। वर्ष 2023 में दर्ज इस मामले में अदालत ने एक किशोर आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। यह सजा सूरत में किसी किशोर को पॉक्सो कानून के तहत दी गई अब तक की सबसे लंबी सजा मानी जा रही है, जिसने पूरे क्षेत्र में कानूनी और सामाजिक स्तर पर गहरी चर्चा को जन्म दिया है। यह मामला फरवरी 2023 में सामने आया था, जब सूरत के सचिन क्षेत्र में रहने वाली एक 12 वर्षीय बालिका के स्वास्थ्य में अचानक गंभीर परिवर्तन देखा गया। बच्ची के परिजनों ने शुरुआत में उसकी शारीरिक कमजोरी को सामान्य मानकर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसे लगातार दो महीनों तक मासिक धर्म नहीं हुआ और पेट में असहनीय दर्द रहने लगा, तब परिवार को स्थिति की गंभीरता का अंदेशा हुआ। चिंतित परिजन उसे तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने आवश्यक जांच की। जांच के परिणाम ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया, क्योंकि रिपोर्ट में बालिका के चार माह की गर्भवती होने की पुष्टि हुई। यह जानकारी सामने आने के बाद परिवार के सदस्यों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने बच्ची से संवेदनशीलता और विश्वास के साथ बातचीत की, जिसके बाद उसने एक दर्दनाक सच्चाई उजागर की। बच्ची ने बताया कि उसके पड़ोस में रहने वाला एक किशोर, जो उस समय 17 वर्ष का था, घर में अकेला पाकर उसके साथ जबरदस्ती करता था। पीड़िता के अनुसार, आरोपी ने तीन अलग-अलग मौकों पर उसके साथ दुष्कर्म किया था। इस खुलासे ने परिवार को झकझोर कर रख दिया और उन्होंने तुरंत

पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

डॉक्टरों की सलाह और परिवार की सहमति से बालिका का सुरक्षित गर्भपात कराया गया, ताकि उसके स्वास्थ्य और भविष्य को सुरक्षित रखा जा सके। इस बीच पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत कार्रवाई शुरू की। पीड़िता के बयान, मेडिकल रिपोर्ट, फॉरेंसिक साक्ष्य और अन्य प्रमाणों के आधार पर आरोपी किशोर को हिरासत में लिया गया और उसे किशोर सुधार गृह भेज दिया गया। मामला किशोर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां विस्तृत सुनवाई के बाद न्यायालय ने सभी साक्ष्यों और परिस्थितियों का गहन विश्लेषण किया।

सरकारी पक्ष की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक मृणाल ब्रह्मभट्ट ने मजबूती के साथ पैरवी की और अदालत के समक्ष यह सिद्ध किया कि आरोपी ने एक मासूम बच्ची के साथ गंभीर और अमानवीय अपराध किया है। अदालत में प्रस्तुत मेडिकल रिपोर्ट, पीड़िता का बयान और अन्य साक्ष्य इतने मजबूत थे कि आरोपी के अपराध को लेकर कोई संदेह नहीं रह गया। अंततः अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद वी. परमार की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।

इस फैसले की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि आरोपी को उसकी वर्तमान आयु और किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सजा की प्रक्रिया लागू की जाएगी। घटना के समय आरोपी की उम्र 17 वर्ष थी, जबकि अब वह 20 वर्ष का हो चुका है। अदालत के आदेश के अनुसार, आरोपी को 21 वर्ष की आयु पूरी होने तक मेहसाणा स्थित किशोर सुधार गृह में रखा जाएगा। इसके बाद उसे शेष सजा नियमित जेल में पूरी करनी होगी। इस प्रकार न्यायालय ने कानून के प्रावधानों का पालन करते हुए अपराध की गंभीरता को भी ध्यान में रखा।

यह फैसला न केवल पीड़िता और उसके परिवार के लिए न्याय का प्रतीक है, बल्कि समाज में यह संदेश भी देता है कि बच्चों के खिलाफ अपराध को किसी भी स्थिति में सहन नहीं किया जाएगा। किशोर न्याय व्यवस्था का मूल उद्देश्य अपराध करने वाले किशोरों का सुधार और पुनर्वास है, लेकिन जब अपराध जघन्य और अमानवीय हो, तो कानून कठोर दंड देने की भी अनुमति देता है। विशेष रूप से 16 से 18 वर्ष की आयु वर्ग में किए गए गंभीर अपराधों के मामलों में अदालत परिस्थितियों के अनुसार कठोर सजा सुना सकती है।

इस मामले ने समाज में बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर प्रश्न भी खड़े किए हैं। यह घटना इस बात का उदाहरण है कि अपराधी अक्सर पीड़ित के आसपास ही होते हैं, जिन्हें परिवार जानता और पहचानता है। ऐसे में माता-पिता और अभिभावकों को अपने बच्चों के व्यवहार, स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। बच्चों के साथ संवाद बनाए रखना, उन्हें सुरक्षित और जागरूक बनाना और किसी भी असामान्य परिस्थिति को गंभीरता से लेना अत्यंत आवश्यक है।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से भविष्य में ऐसे अपराधों पर रोक लगाने में मदद मिलेगी और अपराधियों के मन में कानून का भय उत्पन्न होगा। यह फैसला यह भी दर्शाता है कि न्यायपालिका बच्चों के अधिकारों और सुरक्षा के प्रति अत्यंत संवेदनशील और प्रतिबद्ध है। पॉक्सो कानून का उद्देश्य बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा प्रदान करना है और इस कानून के तहत दोषियों को कठोर दंड दिया जाता है। पीड़िता के परिवार ने अदालत के फैसले पर संतोष व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि यह फैसला उनकी बच्ची के साथ हुए अन्याय के खिलाफ न्याय का प्रतीक है और इससे उन्हें मानसिक शांति मिली है। हालांकि इस घटना ने उनके जीवन पर गहरा प्रभाव छोड़ा है, लेकिन न्याय मिलने से उन्हें यह विश्वास मिला है कि कानून उनके साथ है।

यह मामला समाज के लिए एक चेतावनी भी है कि बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। बच्चों के साथ होने वाले किसी भी प्रकार के अपराध को तुरंत रिपोर्ट करना और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करना आवश्यक है। न्यायालय का यह फैसला यह साबित करता है कि कानून कमजोरों और पीड़ितों की रक्षा के लिए पूरी तरह सक्षम है और अपराधियों को उनके अपराध का उचित दंड अवश्य मिलेगा। इस फैसले ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि उम्र की सीमा अपराध की गंभीरता को कम नहीं कर सकती। यदि कोई किशोर जघन्य अपराध करता है, तो उसे भी कानून के अनुसार कठोर दंड का सामना करना होगा।

संपादकीय

एआई से दोस्ती

तकनीकी विकास के इतिहास में कुछ क्षण ऐसे आते हैं, जब कोई राष्ट्र केवल सहभागी नहीं रहता, बल्कि दिशा निर्धारक बन जाता है। आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के क्षेत्र में भारत जिस प्रकार सक्रियता और दूरदर्शिता के साथ आगे बढ़ रहा है, वह इस बात का संकेत है कि देश आने वाले समय में वैश्विक तकनीकी व्यवस्था का नेतृत्व करने की क्षमता रखता है। इसी दृष्टि से राजधानी नई दिल्ली में आयोजित पांच दिवसीय वैश्विक एआई समिट केवल एक सम्मेलन नहीं, बल्कि भारत की उस महत्वाकांक्षा और रणनीतिक सोच का प्रतीक है, जिसके माध्यम से वह स्वयं को विश्व के एआई केंद्र के रूप में स्थापित करना चाहता है। इस आयोजन में सौ से अधिक बड़ी कंपनियों के सीईओ, अनेक देशों के राष्ट्राध्यक्ष और 135 देशों के प्रतिनिधियों की भागीदारी इस बात का प्रमाण है कि भारत को अब तकनीकी भविष्य का एक विश्वसनीय और निर्णायक भागीदार माना जा रहा है। आज की दुनिया में एआई केवल एक तकनीकी नवाचार नहीं है, बल्कि यह आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक शक्ति का नया स्रोत बन चुका है। जिस देश के पास बेहतर एआई तकनीक, कुशल मानव संसाधन और विशाल डेटा संसाधन होंगे, वही वैश्विक व्यवस्था में प्रभावी भूमिका निभा सकेगा। भारत के पास इन तीनों क्षेत्रों में उल्लेखनीय क्षमता मौजूद है। देश की विशाल जनसंख्या, विशेष रूप से युवाओं की बड़ी संख्या, भारत की सबसे बड़ी ताकत है। भारत दुनिया का सबसे युवा राष्ट्र है, जहां लाखों विद्यार्थी और पेशेवर एआई, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग और रोबोटिक्स जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। यह युवा शक्ति भारत को केवल तकनीकी उपभोक्ता नहीं, बल्कि तकनीकी निर्माता और नवप्रवर्तक बनने की दिशा में अग्रसर कर रही है। इस सम्मेलन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि भारत एआई को केवल आर्थिक लाभ का माध्यम नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन के साधन के रूप में देख रहा है। एआई का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, परिवहन और प्रशासन जैसे क्षेत्रों में व्यापक बदलाव ला सकता है। उदाहरण के लिए, एआई आधारित तकनीक किसानों को मौसम की सटीक जानकारी देकर फसल उत्पादन बढ़ाने में मदद कर सकती है। स्वास्थ्य क्षेत्र में एआई रोगों की शीघ्र पहचान और उपचार को संभव बना सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में एआई छात्रों को उनकी क्षमता और आवश्यकता के अनुसार व्यक्तिगत शिक्षण प्रदान कर सकता है। प्रशासनिक क्षेत्र में एआई भ्रष्टाचार को कम करने, पारदर्शिता बढ़ाने और सरकारी सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाने में सहायक हो सकता है। इस प्रकार एआई आम नागरिकों के जीवन को अधिक सरल, सुरक्षित और समृद्ध बना सकता है। इस सम्मेलन का आयोजन भारत मंडपम जैसे आधुनिक और विश्वस्तरीय स्थल पर किया जा रहा है, जहां लगभग तीन लाख लोगों का पंजीकरण इस आयोजन की लोकप्रियता और महत्व को दर्शाता है। यह संख्या केवल उत्साह का प्रतीक नहीं, बल्कि यह संकेत है कि भारत में एआई को लेकर व्यापक स्तर पर जागरूकता और रुचि बढ़ रही है। यह सम्मेलन भारत को वैश्विक एआई समुदाय के साथ जुड़ने, अनुभव साझा करने और नई साझेदारियां स्थापित करने का अवसर प्रदान कर रहा है। इससे भारत को नवीनतम तकनीकों और सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने में मदद मिलेगी। हाल के वर्षों में विकसित देशों ने एआई के क्षेत्र में तेजी से प्रगति की है और इस तकनीक पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया है। इससे विकासशील देशों में यह चिंता उत्पन्न हुई है कि कहीं एआई तकनीक केवल कुछ शक्तिशाली देशों के हितों की पूर्ति का साधन न बन जाए। ऐसे समय में भारत की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। भारत एक ऐसा मॉडल प्रस्तुत कर सकता है, जिसमें एआई का उपयोग समावेशी विकास और सामाजिक न्याय के लिए किया जाए। भारत का लोकतांत्रिक ढांचा और विविधता इसे एआई के नैतिक और जिम्मेदार उपयोग के लिए एक आदर्श उदाहरण बना सकता है। भारत यह सुनिश्चित कर सकता है कि एआई का लाभ केवल कुछ लोगों तक सीमित न रहे, बल्कि समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। हालांकि, एआई के विकास के साथ कई चुनौतियां भी जुड़ी हुई हैं। एआई के कारण पारंपरिक नौकरियों पर खतरा उत्पन्न हो सकता है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां कार्य दोहराव वाले और स्वचालित किए जा सकते हैं। भारत जैसे देश में, जहां बड़ी संख्या में लोग श्रम आधारित कार्यों पर निर्भर हैं, यह एक गंभीर चिंता का विषय है। इसलिए यह आवश्यक है कि एआई का उपयोग रोजगार सृजन के साधन के रूप में किया जाए, न कि रोजगार समाप्त करने के माध्यम के रूप में। इसके लिए सरकार और उद्योगों को मिलकर ऐसे कार्यक्रम शुरू करने होंगे, जो लोगों को नई तकनीकों के अनुरूप कौशल प्रदान करें। कौशल विकास और पुनः प्रशिक्षण के माध्यम से लोगों को एआई आधारित अर्थव्यवस्था में भागीदारी के लिए तैयार किया जा सकता है।

प्रगतिशील दृष्टि से देखें फिल्मों में अभिव्यक्ति

> “ लीक से हटकर जो किताबें और फिल्में होती हैं, वे हमारे चेतना-तंतुओं को झकझोरने का काम करती हैं। ऐसी किताबें और फिल्में अनेक तरह के सवाल तो उठाती ही हैं, कई पारम्परिक धारणाओं को भी तोड़ती हैं।

क्या हमारे समाज में जाति और धर्म के नाम पर असहिष्णुता और बढ़ रही है? क्या इस दौर में जाति और धर्म के नाम पर लोगों की भावनाएं कुछ ज्यादा ही आहत नहीं होने लगी हैं? ताजा मामला है ‘घूसखोर पंडत’ फिल्म का। हालांकि, अब सुप्रीम कोर्ट ने इस फिल्म का टाइटल बदलने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने विवेक से यह फैसला दिया है। इसलिए इस फैसले पर कोई सवाल नहीं है लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अलग इस मुद्दे पर कई सवाल खड़े होते हैं। एक फिल्म का टाइटल यदि किसी समाज की भावनाएं आहत कर दे तो यह सवाल तो उठेगा कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी क्या हम एक प्रगतिशील समाज बना पाए हैं?

एक काल्पनिक फिल्म और काल्पनिक किरदार यदि किसी समाज की भावनाएं आहत करने की हिम्मत रखता है तो यह सवाल भी उठेगा कि क्या हमारी भावनाएं भी तो काल्पनिक नहीं हो गई हैं। यह केवल ब्राह्मण समाज का मामला नहीं है। आए दिन किसी न किसी मुद्दे पर किसी जाति या किसी धर्म के लोगों की भावनाएं आहत होती रहती हैं। बहरहाल, अब इस फिल्म का टीजर और उससे जुड़ी सभी प्रमोशनल सामग्री नेटफ्लिक्स इंडिया के सोशल मीडिया अकाउंट और यूट्यूब से हटा ली गई हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस मामले में सूचना और प्रसारण मंत्रालय को नोटिस जारी कर दिया है। आयोग ने कहा है कि इस तरह के टाइटल और फिल्म सामग्री से न केवल समुदायों के बीच वैमनस्य बढ़ सकता है, बल्कि सार्वजनिक व्यवस्था को भी खतरा हो सकता है।

हमारे देश में विभिन्न जातियों और धर्मों के लोग रहते हैं। सभी जातियों और धर्मों के लोगों ने इस देश के विकास में अपना योगदान दिया है। जिस तरह अन्य जातियों और समाज के लोगों ने देश में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका

निभाई है उसी तरह ब्राह्मण समाज के लोगों के योगदान को भी भूला नहीं जा सकता। इस फिल्म के टाइटल ‘घूसखोर पंडत’ पर कई लोगों ने आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि ‘पंडित’ शब्द आम तौर पर ब्राह्मण समाज और धार्मिक विद्वानों से जुड़ा होता है लेकिन इसके साथ घूसखोर शब्द जोड़ना गलत है। लोगों का मानना है कि इसमें ब्राह्मण समाज को गलत तरीके से दिखाया है।

सवाल यह है कि अगर फिल्म में किसी एक जाति या समाज से जुड़ा कोई इंसान घूसखोर है और उसे घूसखोर या भ्रष्टाचारी दिखाया गया है और इसका टाइटल भी घूसखोर रखा गया है तो इससे उस पूरी जाति या समाज का अपमान कैसे हो गया? यदि एक चरित्र को उसकी जाति से जोड़कर घूसखोर लिखा गया है तो यह उस चरित्र के बारे में हैं न कि उस पूरे समाज के बारे में है। सवाल यह है कि इसे जानबूझकर एक जाति या समाज से जोड़कर क्यों देखा जा रहा है। इस दौर में हमारी भावनाएं इतनी जल्दी क्यों आहत होने लगती हैं? निश्चित रूप से यह समाज लगातार प्रगति की ओर अग्रसर है लेकिन क्या एक पढ़े-लिखे समाज में हमारी मानसिकता भी बड़ी नहीं होनी चाहिए? क्या संकुचित मानसिकता से वास्तव में हम प्रगतिशील समाज के दायरे में आ पाएंगे? इस दौर में क्या हमारी समझ छोटी हो गई है या फिर हम जानबूझकर समझना नहीं चाहते हैं? कभी कोई किताब हमारी भावनाएं आहत कर देती है तो कभी कोई फिल्म हमारा अपमान कर देती है। क्या वास्तव में हम 21वीं सदी का समाज कहलाने लायक हैं?

हर जाति और धर्म में अच्छे और बुरे लोग होते हैं। अगर अच्छाई और बुराई को हम किसी एक जाति या धर्म से जोड़कर देखने लगेंगे तो बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाएंगी। भ्रष्टाचार करने वाला इंसान किसी भी जाति या धर्म में हो सकता है। अगर किसी जाति या समाज का एक या कुछ इंसान भ्रष्टाचारी हैं तो इस आधार पर वह पूरा समाज भ्रष्टाचारी नहीं हो सकता। दरअसल, इस दौर में शिक्षा का प्रचार-प्रसार हुआ। यह समाज पहले से अधिक पढ़ा-लिखा और प्रगतिशील है।

निःसंदेह, प्रगतिशील दौर में जाति कमजोर होनी चाहिए थी लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि इस दौर में जाति और मजबूत हो गई है। जाति आधारित संगठन भी मजबूत हो रहे हैं। यही कारण है कि हर जाति अपने अपमान की बात करने लगी है। हमें यह समझना होगा कि किसी एक क्रियाकलाप से भला पूरी जाति का अपमान कैसे हो सकता है। इस दौर में भी मजबूत होती जाति प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समाज में वैमनस्य पैदा कर रही है। आए दिन कहीं न कहीं जाति के अपमान के मुद्दे पर हंगामा होता रहता है। सवाल यह है कि क्या एक पढ़े-लिखे समाज में इस तरह की मानसिकता उचित है? निश्चित रूप से एक पढ़े-लिखे समाज से इस तरह के व्यवहार की उम्मीद नहीं की जा सकती।

आलोचना होती है, भारतीय समाज अभी तक भी किताबों को पढ़ने और फिल्मों को देखने की प्रगतिशील सोच की समझ विकसित नहीं कर पाया है। लीक से हटकर जो किताबें और फिल्में होती हैं, वे हमारे चेतना-तंतुओं को झकझोरने का काम करती हैं। ऐसी किताबें और फिल्में अनेक तरह के सवाल तो उठाती ही हैं, कई पारम्परिक धारणाओं को भी तोड़ती हैं। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि हम अपने अंदर झांकने के बजाय ऐसी किताबों और फिल्मों को ही कठघरे में खड़ा करने लगते हैं। यही कारण है कि भावनाएं आहत होने के नाम पर या फिर समाज का अपमान होने के नाम पर किताबों और फिल्मों पर रोक लगाने की मांग अक्सर उठती रहती है। इस दौर में हमारे समाज में जाति और धर्म के नाम पर जिस तरह की नफरत फैलाई जा रही है, वह हमें अंधकार में धकेल रही है। अपनी मानसिकता को बदलकर ही भारतीय समाज इस अंधकार को दूर कर सकता है।

प्रेरणा

संतोष और संयम से ही धन का वास्तविक सुख

मनुष्य के जीवन में धन का स्थान महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उसकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति का माध्यम है। बिना धन के जीवन की सामान्य व्यवस्था भी कठिन हो जाती है। भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी आवश्यकताओं के लिए धन की जरूरत होती है। इसलिए धन अर्जित करना मनुष्य का कर्तव्य और अधिकार दोनों है। लेकिन जब धन का महत्व आवश्यकता से अधिक बढ़ जाता है और वह जीवन का अंतिम लक्ष्य बन जाता है, तब वही धन मनुष्य के दुख, चिंता और असंतोष का कारण बन जाता है। संतों और महापुरुषों ने सदैव यही संदेश दिया है कि धन का अर्जन आवश्यक है, लेकिन उससे भी अधिक आवश्यक है उसका संयमित उपयोग और संतुलित दृष्टिकोण।

एक बार एक संत अपने आश्रम में शिष्यों को जीवन का सार समझा रहे थे। आश्रम का वातावरण शांत और पवित्र था। शिष्य संत के चारों ओर बैठे हुए उनकी वाणी को ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। संत ने कहा कि मनुष्य को अपने पुरुषार्थ और परिश्रम से धन अर्जित करना चाहिए, क्योंकि यह उसके कर्म का फल है। लेकिन धन के प्रति आसक्ति और अति संग्रह मनुष्य को उसके वास्तविक उद्देश्य से दूर कर देता है। धन इतना ही होना चाहिए, जिससे जीवन सुचारु रूप से चल सके और आवश्यकता के समय सहारा मिल सके। धन का संग्रह केवल संग्रह करने के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका उपयोग जीवन और समाज के कल्याण के लिए होना चाहिए।

संत ने वैदिक विचारों का उल्लेख करते हुए कहा कि संयम ही जीवन का सबसे बड़ा आभूषण है। जिस मनुष्य में संयम होता है, वह सीमित साधनों में भी संतुष्ट और प्रसन्न रहता है। इसके विपरीत, जिस मनुष्य में संयम नहीं होता, वह असीमित धन प्राप्त करने के बाद भी असंतुष्ट रहता है। उसकी इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होतीं, और वह हमेशा अधिक पाने की लालसा में जीता रहता है। यह लालसा ही उसके दुख का कारण बन जाती है। धन का वास्तविक सुख तभी प्राप्त होता है, जब उसके साथ संतोष और संयम भी हो।

संत के इन विचारों को सुनकर शिष्यों के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। कुछ शिष्यों ने सोचा कि यदि धन मेहनत से कमाया गया है और उसे सुरक्षित रखा जा सकता है, तो इसमें क्या बुराई है। उनका मानना था कि भविष्य की अनिश्चितताओं से बचने के लिए अधिक से अधिक धन का संग्रह करना बुद्धिमानी है। एक शिष्य ने साहस करके संत से यही प्रश्न पूछ लिया कि यदि कोई व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से धन अर्जित करता है और उसे सुरक्षित रूप से संग्रह करता है, तो क्या यह गलत है?

संत ने शिष्य की ओर प्रेम और करुणा से देखा और मुस्कुराते हुए कहा कि धन का संग्रह करना गलत नहीं है, लेकिन संग्रह के पीछे की भावना और उद्देश्य महत्वपूर्ण है। उन्होंने समझाया कि यदि धन का संग्रह केवल संग्रह करने के लिए किया जाए, तो वह अंततः व्यर्थ सिद्ध होता है। उन्होंने एक उदाहरण देकर अपनी बात स्पष्ट की। संत ने कहा कि मधुमक्खियां दिन-रात परिश्रम करके फूलों से पराग एकत्र करती हैं और उससे शहद बनाती हैं। वे अपने जीवन का अधिकांश समय शहद के संग्रह में लगा देती हैं। लेकिन अंततः उस शहद का उपयोग अक्सर अन्य जीव और मनुष्य करते हैं। मधुमक्खियों का परिश्रम महान होता है, लेकिन वे अपने संग्रह का पूरा लाभ स्वयं नहीं उठा पातीं।

इसी प्रकार, यदि मनुष्य केवल धन के संग्रह में लगा रहता है और उसका उपयोग न तो अपने जीवन को सार्थक बनाने में करता है और न ही दूसरों के कल्याण में, तो उसका संग्रह भी अंततः किसी और के काम ही आता है। धन का वास्तविक महत्व उसके सदुपयोग में है, न कि उसके संग्रह में। यदि धन से किसी जरूरतमंद की सहायता की जा सके, किसी दुखी के जीवन में सुख लाया जा सके, या समाज के विकास में योगदान दिया जा सके, तो वही धन सार्थक है।

संत ने आगे कहा कि धन के प्रति अत्यधिक मोह मनुष्य को भय और चिंता से भर देता है। वह हमेशा अपने धन की सुरक्षा को लेकर चिंतित रहता है। उसे यह डर सताता है कि कहीं उसका धन नष्ट न हो जाए या कोई उसे छीन न ले। इस प्रकार धन, जो सुरक्षा का साधन होना चाहिए, वही असुरक्षा का कारण बन जाता है। इसके विपरीत, जो मनुष्य संयम और संतोष के साथ धन का उपयोग करता है, वह मानसिक शांति और सुख का अनुभव करता है। मनुष्य को यह समझना चाहिए कि जीवन का उद्देश्य केवल धन अर्जित करना नहीं है। जीवन का वास्तविक उद्देश्य आत्मिक विकास, सेवा, प्रेम और संतोष प्राप्त करना है। धन इन उद्देश्यों की प्राप्ति का एक साधन हो सकता है, लेकिन यह स्वयं उद्देश्य नहीं है। यदि मनुष्य धन को साधन के रूप में उपयोग करता है, तो वह सुखी और संतुष्ट रहता है। लेकिन यदि वह धन को ही लक्ष्य बना लेता है, तो वह कभी संतुष्ट नहीं हो सकता।

संत ने यह भी कहा कि धन का एक अंश परोपकार में लगाना चाहिए। जरूरतमंदों की सहायता करना, समाज के कल्याण में योगदान देना और दूसरों के जीवन में सुख लाना ही धन का सर्वोत्तम उपयोग है। ऐसा करने से न केवल समाज को लाभ होता है, बल्कि मनुष्य को भी आत्मिक संतोष और शांति प्राप्त होती है। यह संतोष किसी भी भौतिक सुख से अधिक मूल्यवान होता है।

जीवन की सच्चाई यह है कि मनुष्य इस संसार में खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही जाता है। वह अपने साथ केवल अपने कर्मों का फल लेकर जाता है। इसलिए धन का संग्रह करते समय यह स्मरण रखना चाहिए कि उसका उपयोग जीवन को सार्थक बनाने के लिए होना चाहिए। संयम और संतोष के साथ अर्जित और उपयोग किया गया धन ही वास्तविक सुख और शांति प्रदान करता है।

संत की इन शिक्षाओं ने शिष्यों के हृदय को स्पर्श किया। उन्होंने समझ लिया कि धन का संग्रह आवश्यक है, लेकिन उससे भी अधिक आवश्यक है उसका संयमित उपयोग और सदुपयोग। उस दिन के बाद शिष्यों ने न केवल धन अर्जित करने का प्रयास किया, बल्कि उसका उपयोग विवेक, संयम और परोपकार की भावना के साथ करना भी सीखा।

आज के समय में, जब मनुष्य धन के पीछे भागते-भागते अपने जीवन की शांति खोता जा रहा है, संत की यह शिक्षा अत्यंत प्रासंगिक है। यदि मनुष्य संयम, संतोष और परोपकार के मार्ग पर चलता है, तो वह न केवल स्वयं सुखी और संतुष्ट रहेगा, बल्कि समाज को भी सुख और समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ा सकेगा। यही धन का वास्तविक उद्देश्य है और यही जीवन का सच्चा सुख है।

सीधे भारत मंडपम से... क्या AI के क्षेत्र में दुनिया को पछाड़ पाएगा भारत?

दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित हो रहे वैश्विक एआई सम्मेलन में दो दिन से चल रहे विचार मंथन से एक बात उभर कर आई है कि एआई के समक्ष खड़ी चुनौतियों के हल के लिए दुनिया भारत की ओर निहार रही है। देखना होगा कि सम्मेलन के अंत में दिल्ली डिक्लेरेशन से क्या निकल कर आता है। लेकिन यहां एक ओर बात की आवश्यकता महसूस हुई कि भारत को यदि इस क्षेत्र में नेतृत्व हासिल करना है तो बड़े निवेश और सरल तथा प्रभावी नीतियों की भी जरूरत है। देखा जाए तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई अब केवल नई तकनीक का आकर्षण नहीं रही, बल्कि यह अर्थव्यवस्था, उद्योग, ऊर्जा, नीति और वैश्विक शक्ति संतुलन का केंद्र बन चुकी है। दुनिया के बड़े देश इसे रणनीतिक साधन की तरह देख रहे हैं। डाटा, कंप्यूटिंग शक्ति और उन्नत चिप आज के दौर का नया तेल बन चुके हैं। ऐसे समय में भारत के सामने मूल प्रश्न यह है कि वह एआई की दौड़ में केवल उपभोक्ता बन कर रहेगा या निर्माता और नेता की भूमिका निभाएगा। भारत ने पहले भी तकनीकी मोड़ पर सही फैसले लेकर इतिहास बदला है। नब्बे के दशक में सूचना तकनीक और सॉफ्टवेयर सेवाओं पर जोर देने से लाखों रोजगार बने, भारतीय कंपनियां दुनिया भर में छा गईं और देश को नई पहचान मिली। आज एक वैसा ही मोड़ फिर सामने है, लेकिन इस बार दांव कहीं बड़ा है। एआई न केवल सेवाओं को, बल्कि कारखानों, आपूर्ति श्रृंखलाओं, दवा उद्योग, परिवहन और ऊर्जा व्यवस्था तक को बदल सकती है। यह समझना जरूरी है कि एआई एक ही तरह की चीज नहीं है। उपभोक्ता एआई, जैसे चैट टूल या मनोरंजन आधारित अनुप्रयोग, तेजी से लोकप्रिय होते हैं, पर इन पर अक्सर कुछ ही बड़ी कंपनियों का दबदबा हो जाता है। इसके विपरीत औद्योगिक एआई हर क्षेत्र के लिए अलग समाधान मांगती है। हर उद्योग का अपना डाटा, अपनी समस्या और अपना कामकाज होता है। इसलिए क्षेत्र विशेष मॉडल बनते हैं। यही भारत की ताकत बन सकती है, क्योंकि यहां उद्योगों की विविधता और पैमाना दोनों मौजूद हैं।

उदाहरण के लिए दो पहिया वाहन उद्योग को लें। भारत दुनिया के सबसे बड़े दो पहिया बाजारों में है। यह क्षेत्र रोजगार, शहरीकरण और आय वृद्धि से जुड़ा है। अब इलेक्ट्रिक दो पहिया का चलन भी बढ़ रहा है। ऐसे में एआई आधारित मांग अनुमान, डिजाइन सुधार, गुणवत्ता जांच और आपूर्ति प्रबंधन से भारी लाभ हो सकता है। मशीन लर्निंग सिस्टम खराबी का पहले ही संकेत दे सकते हैं। इससे ठहराव घटता है, लागत कम होती है और उत्पादन तेज होता है। दवा उद्योग में भी अवसर विशाल हैं। भारत जेनेरिक दवाओं का बड़ा उत्पादक है, पर गुणवत्ता बनाए रखना चुनौती रहता है। एआई आधारित विजन सिस्टम उत्पादन के दौरान सूक्ष्म दोष पकड़ सकते हैं। डाटा विश्लेषण से प्रक्रिया स्थिर रखी जा सकती है। रोबोटिक ऑटोमेशन दोहराव वाले काम सुरक्षित और सटीक तरीके से कर सकता है। इससे भारत की विश्वसनीयता बढ़ेगी और ऊंचे मूल्य वाले बाजार खुलेंगे। लेकिन एआई की ताकत केवल सॉफ्टवेयर से नहीं आती, इसके लिए भारी कंप्यूटिंग शक्ति चाहिए, जो उन्नत चिप यानी जीपीयू से मिलती है। ये चिप बहुत महंगी होती हैं। एक उन्नत जीपीयू की कीमत लाखों रुपये तक जा सकती है। भारत ने हजारों जीपीयू लगाए हैं और डाटा केंद्र तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले वर्ष डाटा केंद्रों ने बिजली ग्रिड से भारी मात्रा में बिजली ली, जो किसी बड़े शहर की मांग के बराबर बैठती है। आने वाले वर्षों में यह मांग कई गुना बढ़ सकती है। यह भारत की बढ़ती डिजिटल क्षमता का संकेत है, पर साथ ही ऊर्जा चुनौती का भी।

अगर भारत को एआई में अग्रणी बनना है तो केवल कुछ हजार जीपीयू काफी नहीं होंगे। अमेरिका आज भी इस क्षेत्र में आगे है। उसके पास विशाल डाटा केंद्र क्षमता है और वह उन्नत जीपीयू की आपूर्ति पर नियंत्रण रखता है। इसी कारण वह तकनीकी बढ़त बनाए हुए है। चीन को रोकने की रणनीति में भी चिप आपूर्ति अहम रही है।

चीन ने भी इस दौड़ को बहुत पहले समझ लिया था। उसने चिप निर्माण में भारी निवेश किया। उसकी बड़ी तकनीकी कंपनियां अपने एआई चिप बना रही हैं। भले वे अभी सबसे उन्नत स्तर पर न हों, पर तेजी से आगे बढ़ रही हैं। अमेरिका में भी बड़ी तकनीकी कंपनियां खुद चिप डिजाइन में उतर चुकी हैं। ऐसे माहौल में यदि भारत केवल पुराने स्तर की चिप बनाता रह गया तो वह पीछे छूट सकता है। तो क्या समाधान है? क्या हमें अपनी आकांक्षा घटा लेनी चाहिए? कुछ लोग कहते हैं कि भारत की प्रति व्यक्ति बिजली खपत अभी विकसित देशों से कम है। जैसे जैसे लोग समृद्ध होंगे, उन्हें घरों में अधिक बिजली चाहिए होगी। अगर एआई के कारण बिजली महंगी हुई तो जीवन स्तर प्रभावित हो सकता है। यह चिंता सही है, पर इसका मतलब यह नहीं कि हम पीछे हट जाएं। दरअसल जरूरत बड़े सोच की है। भारत को एक साथ दो मोर्चों पर काम करना होगा। पहला, घरेलू चिप निर्माण और डिजाइन को बढ़ावा देना। इसके लिए नीति समर्थन, निवेश और कौशल विकास जरूरी है। दूसरा, ऊर्जा ढांचा मजबूत करना। नवीकरणीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, बेहतर ग्रिड और भंडारण तकनीक पर जोर देना होगा ताकि डाटा केंद्रों की मांग पूरी हो सके।

अभियान

मंगल दोष से मुक्ति का दिव्य द्वार: उज्जैन के मंगलनाथ मंदिर की भात पूजा का चमत्कार

भारतीय ज्योतिष परंपरा में मंगल ग्रह को अत्यंत प्रभावशाली और ऊर्जावान ग्रह माना गया है। यह ग्रह मनुष्य के साहस, पराक्रम, ऊर्जा, भूमि, संपत्ति और वैवाहिक जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। मंगल को भूमि पुत्र भी कहा जाता है, क्योंकि इसका संबंध पृथ्वी और स्थिरता से जोड़ा गया है। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल अनुकूल स्थिति में होता है, तो वह व्यक्ति साहसी, आत्मविश्वासी और सफल होता है, लेकिन जब मंगल प्रतिकूल हो जाता है, तब उसे मंगल दोष या मांगलिक दोष कहा जाता है। यह दोष व्यक्ति के जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न कर सकता है, जैसे विवाह में देरी, वैवाहिक जीवन में तनाव, आर्थिक संकट, मानसिक अशांति, क्रोध की अधिकता और पारिवारिक कलह। ऐसे में भारतीय धार्मिक परंपरा में कुछ विशेष स्थानों और उपायों का उल्लेख मिलता है, जहां मंगल दोष का प्रभाव कम करने के लिए विशेष पूजा और अनुष्ठान किए जाते हैं। इन पवित्र स्थानों में सबसे प्रमुख और प्रभावशाली स्थान मंगलनाथ मंदिर है, जो पवित्र नगरी उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर स्थित है।

यह मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि यह आस्था, विश्वास और ज्योतिषीय ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यही वह स्थान है जहां मंगल देव का जन्म हुआ था। यही कारण है कि इस मंदिर को मंगल ग्रह की शांति और मंगल दोष निवारण के लिए विश्व का सबसे महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। यहां प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु आते हैं, लेकिन मंगलवार के दिन यहां विशेष भीड़ होती है, क्योंकि यह दिन मंगल देव को समर्पित माना जाता है। श्रद्धालु यहां आकर विशेष रूप से भात पूजा करते हैं, जो इस मंदिर की सबसे अनोखी और प्रभावशाली परंपरा है।

भात पूजा का महत्व अत्यंत गहरा और आध्यात्मिक है। इस पूजा में भगवान मंगल को चावल अर्पित किए जाते हैं। चावल की प्रकृति शीतल होती है, जबकि मंगल ग्रह की प्रकृति उग्र और अग्नि तत्व से संबंधित मानी जाती है। जब श्रद्धालु मंगल देव को चावल अर्पित करते हैं, तो यह मंगल की उग्रता को शांत करने और जीवन में संतुलन स्थापित करने का प्रतीक माना जाता है। ज्योतिषीय दृष्टि से यह पूजा मंगल दोष के नकारात्मक प्रभावों को कम करने और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाने का एक प्रभावी उपाय माना गया है। इस पूजा के दौरान श्रद्धालु पूरे विधि-विधान से मंत्रोच्चार करते हैं और मंगल देव से अपने जीवन की बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना करते हैं।

मंगलनाथ मंदिर का वातावरण अत्यंत पवित्र और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ होता है। जब श्रद्धालु यहां पूजा करते हैं, तो उन्हें एक विशेष प्रकार की मानसिक शांति और आत्मिक संतुलन की अनुभूति होती है। यह केवल धार्मिक आस्था का परिणाम नहीं है, बल्कि यह उस विश्वास की शक्ति है, जो मनुष्य को उसकी कठिनाइयों से लड़ने की प्रेरणा देती है। इस मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं का मानना है कि यहां की गई पूजा से उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आता है और उनके सामने आने वाली बाधाएं धीरे-धीरे समाप्त होने लगती हैं। मंगल ग्रह का संबंध केवल विवाह और पारिवारिक जीवन से ही नहीं, बल्कि भूमि, संपत्ति और साहस से भी होता है। जिन लोगों की कुंडली में मंगल दोष होता है, उन्हें अक्सर भूमि संबंधी विवाद, आर्थिक कठिनाइयों और मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है। ऐसे लोगों के लिए मंगलनाथ मंदिर में पूजा करना विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। यहां की भात पूजा व्यक्ति के जीवन में स्थिरता, संतुलन और सकारात्मक ऊर्जा लाने में सहायक मानी जाती है।

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मंगल देव का संबंध भगवान शिव से भी है। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि मंगल देव का जन्म भगवान शिव के तेज से हुआ था। यही कारण है कि मंगल दोष के निवारण के लिए भगवान शिव की पूजा भी अत्यंत प्रभावी मानी जाती है। मंगलनाथ मंदिर में श्रद्धालु शिव और मंगल दोनों की पूजा करते हैं, जिससे उन्हें दोहरी आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है।

मंगल दोष के निवारण के लिए केवल मंदिर में पूजा करना ही पर्याप्त नहीं माना गया है, बल्कि कुछ अन्य धार्मिक उपाय भी बताए गए हैं। मंगलवार के दिन भगवान हनुमान की पूजा करना विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है, क्योंकि हनुमान जी को मंगल का इष्ट देव माना गया है। हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करने से व्यक्ति के जीवन में साहस, आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह उपाय व्यक्ति के मानसिक तनाव को कम करता है और उसे जीवन की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देता है। इसके अलावा मंगलवार के दिन लाल वस्त्र, लाल मसूर की दाल, गुड़ और तांबे की वस्तुओं का दान करना भी शुभ माना जाता है। यह दान मंगल ग्रह को प्रसन्न करने और उसके नकारात्मक प्रभावों को कम करने का प्रतीक माना जाता है। मंत्र जाप भी मंगल दोष के निवारण में अत्यंत प्रभावी माना गया है। ‘ऊँ भौमाय नमः’ और ‘ऊँ अंगारकाय नमः’ मंत्र का नियमित जाप करने से व्यक्ति के जीवन में मानसिक शांति और संतुलन आता है।

मंगल दोष से पीड़ित लोगों के लिए मंगलवार का व्रत रखना भी अत्यंत लाभकारी माना गया है। कम से कम 21 मंगलवार तक व्रत रखने से मंगल दोष का प्रभाव कम होता है और विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। इस व्रत के दौरान व्यक्ति नमक का सेवन नहीं करता और शाम को भगवान हनुमान को भोग लगाकर फलाहार करता है। यह व्रत केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह आत्मसंयम और आत्मशुद्धि का भी प्रतीक है।

मंगलनाथ मंदिर का महत्व केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। उज्जैन प्राचीन काल से ही ज्योतिष और खगोल विज्ञान का केंद्र रहा है। यहां से समय और ग्रहों की गति की गणना की जाती थी। यह स्थान भारतीय ज्ञान और विज्ञान की महान परंपरा का प्रतीक है। मंगलनाथ मंदिर इस महान परंपरा का जीवंत उदाहरण है, जो आज भी लोगों के जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा और विश्वास का संचार कर रहा है।

आज के आधुनिक युग में, जब मनुष्य अनेक प्रकार की मानसिक और सामाजिक समस्याओं से जूझ रहा है, ऐसे में मंगलनाथ मंदिर जैसे आध्यात्मिक केंद्र उसे आशा और विश्वास प्रदान करते हैं। यहां आने वाले श्रद्धालु केवल पूजा ही नहीं करते, बल्कि अपने जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति भी प्राप्त करते हैं। यह मंदिर उन्हें यह विश्वास दिलाता है कि सच्ची श्रद्धा, विश्वास और सकारात्मक सोच से जीवन की किसी भी समस्या का समाधान संभव है।

मंगलनाथ मंदिर की भात पूजा केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि यह आस्था, विश्वास और आध्यात्मिक संतुलन का प्रतीक है। यह पूजा व्यक्ति के मन को शांत करती है, उसकी नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करती है और उसे जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। यही कारण है कि यह मंदिर आज भी लाखों श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ है।

अंततः यह कहा जा सकता है कि उज्जैन का मंगलनाथ मंदिर केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि एक दिव्य ऊर्जा का स्रोत है, जहां श्रद्धालु अपने जीवन की समस्याओं का समाधान खोजने आते हैं। यहां की भात पूजा और मंगल देव की आराधना व्यक्ति के जीवन में संतुलन, शांति और समृद्धि लाने में सहायक मानी जाती है। यह मंदिर हमें यह सिखाता है कि जब मनुष्य सच्चे विश्वास और श्रद्धा के साथ ईश्वर की शरण में जाता है, तो उसके जीवन की सबसे कठिन बाधाएं भी दूर हो सकती हैं, और उसका जीवन सुख, शांति और सफलता से भर सकता है। यही इस पवित्र स्थान की सबसे बड़ी महिमा और इसकी अनंत आध्यात्मिक शक्ति का प्रमाण है।

RNI No. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, “Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, “Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

'स्वस्थ धरा, खेत हरा' : गुजरात के 2.19 करोड़ किसानों मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित

▸▸ गुजरात में 19 मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं तथा ग्राम स्तर पर 26 निजी मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं कार्यरत
▸▸ 2024-25 में एसएचसी पोर्टल के आधार पर 6,23,844 मिट्टी के नमूने एकत्रित, जिनमें से 6,23,295 नमूनों का हुआ विश्लेषण

(जीएनएस)। गांधीनगर : गुजरात के सर्वांगीण विकास में कृषि विकास एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। राज्य का सर्वांगीण कृषि विकास गुजरात सरकार की प्राथमिकता रही है। यदि खेती योग्य भूमि की समुचित देखभाल न की जाए, तो वह धीरे-धीरे बंजर बन जाती है। भूमि के बंजर होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि प्रदूषण, भूमि में बढ़ती लवणता और रासायनिक उर्वरकों एवं दवाइयों का अत्यधिक इस्तेमाल आदि। गुजरात के अनेक क्षेत्रों में भी यह समस्या सिर उठा रही थी। गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और मौजूदा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इस समस्या के समाधान के लिए एक अभिनव दृष्टिकोण अपनाते हुए वर्ष 2003-04 में 'सॉइल हेल्थ कार्ड योजना' यानी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना (एसएचसी) लागू की। मिट्टी की सेहत की अहमियत को समझते हुए इस प्रकार की अनोखी योजना लागू करने वाला गुजरात देश का पहला राज्य बन गया।

प्रधानमंत्री की दूरदर्शी पहल को आगे बढ़ाते हुए और 'विकसित भारत' के विजन को 'विकसित गुजरात' के जरिए साकार करने की दिशा में सदैव अग्रसर रहा गुजरात मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के मजबूत नेतृत्व में कृषि क्षेत्र मं निरंतर प्रगति कर रहा है। किसानों की आय बढ़ाकर उन्हें सशक्त बनाने के लिए तथा कृषि फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने अनेक किसान-उन्मुख योजनाएं कार्यान्वित की हैं। 'स्वस्थ धरा, खेत रहा' मंत्र के साथ लागू की गई मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के अंतर्गत अब तक गुजरात के 2.19 करोड़ किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं।

गुजरात में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का व्यापक क्रियान्वयन

गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में वर्ष 2003-04 में लॉन्च की गई मृदा स्वास्थ्य कार्ड (एसएचसी) योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी भूमि की स्थिति के संबंध में व्यापक जानकारी प्रदान कर उन्हें सशक्त करना था। एसएचसी योजना का पहला चरण 2003-04 से 2010-11 के दौरान और दूसरा चरण 2011-12 से 2015-16 के दौरान पूर्ण किया गया। पहले चरण में गुजरात के 43.03 लाख से अधिक किसानों और दूसरे चरण में लगभग 46.92 लाख से अधिक किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड निःशुल्क प्रदान किए गए। गुजरात में मिली सफलता के बाद, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2015-16 में देश भर में 'मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना' लागू की। जिसके अंतर्गत तीसरे चरण में वर्ष 2016-17 से अब तक राज्य के 1.25 करोड़ से अधिक किसानों को भारत सरकार की इस योजना के तहत मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए हैं। पिछले एक दशक में, इस योजना के कारण किसानों को उनके खेतों में मिट्टी की पोषक स्थिति की कमी के बारे में पता चला है, साथ ही उन्होंने सूक्ष्म पोषक तत्वों वाले उर्वरकों का उपयोग भी बढ़ाया है। अरवल्ली जिले के धनसुरा शहर के किसान बाबूभाई वसरामभाई पटेल ने बताया कि एसएचसी योजना के तहत उन्हें केवल आवश्यक खाद का सीमित मात्रा में इस्तेमाल करने की सलाह दी गई, जिसका अनुसरण करने के फलस्वरूप उन्हें खाद का खर्च कम करने में मदद मिली। इस पहल से उनकी पैदावार बेहतर हुई और इनपुट लागत में भी कमी आई है।

सरकार प्रयोगशाला की क्षमता और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए प्रयासरत

वर्ष 2024-25 में एसएचसी पोर्टल के आधार पर 6,23,844 मिट्टी के नमूने ऑनलाइन एकत्रित किए गए और 6,23,295 नमूनों का विश्लेषण किया गया। एसएचसी योजना के तहत वर्ष 2025-26 में भारत सरकार ने गुजरात के लिए 6,25,513 नमूनों के परीक्षण का लक्ष्य निर्धारित किया है। गुजरात सरकार भी इस लक्ष्य को तय समय पर हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार ने अब तक 6,13,355 नमूने एकत्रित कर लिए हैं, जिनमें से 4,86,142 नमूनों का विश्लेषण पूरा हो चुका है। शेष नमूनों के परीक्षण का कार्य प्रगति पर है। इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए तथा समय पर विश्लेषण करके मृदा स्वास्थ्य कार्ड का समय पर वितरण सुनिश्चित करने के लिए मृदा परीक्षण प्रयोगशाला की क्षमता और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए सरकार के प्रयास जारी हैं। अभी गुजरात में कृषि विभाग के अंतर्गत मिट्टी के नमूनों के विश्लेषण के लिए कुल 19 मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं तथा 01 सूक्ष्म तत्व परीक्षण प्रयोगशाला कार्यरत हैं। प्रत्येक प्रयोगशाला की क्षमता सालाना 10 से 11 हजार नमूनों का परीक्षण करने की है। इस क्षमता को बढ़ाने के लिए सरकारी सहायता से 26 निजी मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं यानी ग्राम स्तरीय प्रयोगशालाएं भी स्थापित की गई हैं। प्रत्येक निजी प्रयोगशाला भी सालाना 3,000 मिट्टी के नमूनों का परीक्षण करने के लिए तैयार है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना किसानों को उनके खेतों की मिट्टी को प्रभावी ढंग से समझने और उसमें सुधार करने, मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने, उत्पादकता बढ़ाने और उनकी भूमि के अनुरूप फसल उगाने में मदद करती है। इसके अलावा, यह योजना इनपुट लागत को कम करती है और आर्थिक लाभ में वृद्धि के साथ ही खेती के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण को भी बढ़ावा देती है।

क्या है मृदा स्वास्थ्य कार्ड

मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के अंतर्गत खेती योग्य भूमि की सेहत को बरकरार रखने के लिए निर्धारित पद्धति के अनुसार किसानों के खेत से मिट्टी के नमूने लिए जाते हैं और उन्हें विश्लेषण के लिए मृदा परीक्षण प्रयोगशाला भेजा जाता है। जहां, नमूनों का विश्लेषण कर, सॉफ्टवेयर आधारित मृदा स्वास्थ्य कार्ड तैयार किए जाते हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड मिट्टी में मौजूद विभिन्न पोषक तत्वों की मात्रा दर्शाता है, जिसमें वर्तमान में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, जिंक, लौह तत्व, तांबा, मैंगनीज, बोरन, पीएच (अम्लता या क्षारीयता), ईसी (विद्युत चालकता) और ओसी (कार्बनिक कार्बन) जैसे कुल 12 तत्वों की मात्रा दर्शाई जाती है। इसके आधार पर, मृदा स्वास्थ्य कार्ड के जरिए किसानों को सही रासायनिक खाद के प्रयोग और उसकी सटीक मात्रा की वैज्ञानिक सिफारिश मुफ्त में मिलती है। इस प्रक्रिया से अनावश्यक रासायनिक खादों का अत्यधिक इस्तेमाल कम होता है और भूमि की उर्वरता को बनाए रखने में सहायता मिलती है।

भारत–यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता (FTA) संपन्न: भारत की वैश्विक व्यापार सहभागिता में एक रणनीतिक उपलब्धि

(जीएनएस)। 16वें भारत–यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन में माननीय प्रधानमंत्री श्री Narendra Modi एवं यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष महामहिम सुश्री Ursula von der Leyen द्वारा ऐतिहासिक घोषणा

विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत और दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यूरोपीय संघ (जो वैश्विक जीडीपी का 25% हिस्सा है) के बीच विश्वसनीय साझेदारी का सुदृढ़ निर्माण

अभूतपूर्व बाज़ार पहुँचः भारत के 99% से अधिक निर्यात को यूरोपीय संघ में वरीयतापूर्ण प्रवेश, व्यापक विकास की संभावनाएँ

एमएसएमई, महिला, कारीगर, युवा एवं पेशेवरों के लिए नए अवसरों का सृजन

6.41 लाख करोड़ (75 अरब अमेरिकी डॉलर) के निर्यात को गति; वस्त्र, चमड़ा, समुद्री उत्पाद, रत्न एवं आभूषण जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों के लगभग 33 अरब अमेरिकी डॉलर के निर्यात को विशेष लाभ

संतुलित एवं चरणबद्ध ऑटो उदारीकरण से "मेक इन इंडिया" को बढ़ावा

कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात के लिए अनुकूल बाज़ार पहुँच

संवेदनशील कृषि एवं डेयरी क्षेत्रों की सुरक्षा—कोई बाज़ार पहुँच नहीं

सेवाओं में महत्वाकांक्षी एवं वाणिज्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बाज़ार पहुँच

कुशल एवं अर्ध-कुशल भारतीय पेशेवरों के लिए वैश्विक अवसरों का विस्तार

सीबीएएम (CBAM) प्रावधानों के माध्यम से रचनात्मक संवाद और सहयोग सुनिश्चित

भारत–ईयू एफटीए समावेशी, सुदृढ़ और भविष्य उन्मुख विकास की आधारशिला रखता है

माननीय प्रधानमंत्री श्री Narendra Modi और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष महामहिम सुश्री Ursula von der Leyen ने आज 16वें भारत–यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के अवसर पर भारत–यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते (India–EU FTA) के संपन्न होने की संयुक्त घोषणा की। यह घोषणा भारत–ईयू आर्थिक संबंधों और प्रमुख वैश्विक साझेदारों के साथ भारत की व्यापारिक सहभागिता में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है।

यह समझौता भारत और यूरोपीय संघ को खुले बाज़ार, पूर्वानुमेयता और समावेशी विकास के प्रति प्रतिबद्ध विश्वसनीय साझेदार के रूप में स्थापित करता है। वर्ष 2022 में वार्ताओं के पुनः प्रारंभ होने के बाद गहन चर्चाओं के उपरांत यह समझौता संपन्न हुआ, जो संतुलित, आधुनिक और नियम-आधारित आर्थिक साझेदारी की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

यूरोपीय संघ भारत का प्रमुख व्यापारिक भागीदार है। वर्ष 2024–25 में भारत–ईयू के बीच वस्तुओं का द्विपक्षीय व्यापार 11.5 लाख करोड़ (136.54 अरब अमेरिकी डॉलर) रहा, जिसमें 6.4 लाख करोड़ (75.85 अरब डॉलर) का निर्यात और 5.1 लाख करोड़ (60.68 अरब डॉलर) का आयात शामिल है। सेवाओं का व्यापार वर्ष 2024 में 7.2 लाख करोड़ (83.10 अरब डॉलर) रहा।

भारत और यूरोपीय संघ क्रमशः विश्व की चौथी और दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएँ हैं तथा वैश्विक व्यापार का लगभग एक-तिहाई हिस्सा रखते हैं। इन दोनों विविध और पूरक अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण अभूतपूर्व व्यापार एवं निवेश अवसरों का सृजन करेगा।

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री Piyush Goyal ने माननीय प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि यह समझौता भारत की वैश्विक आर्थिक दृष्टि में एक निर्णायक उपलब्धि है। यह "मेक इन इंडिया" पहल को सुदृढ़ करेगा तथा 99% से अधिक भारतीय निर्यात को अभूतपूर्व बाज़ार पहुँच प्रदान करेगा।

यह समझौता वस्तुओं, सेवाओं, व्यापार उपायों, उत्पत्ति के नियम, सीमा शुल्क और व्यापार सुगमता जैसे पारंपरिक क्षेत्रों के साथ-साथ एमएसएमई और डिजिटल व्यापार जैसे उभरते क्षेत्रों को भी शामिल करता है।

वस्त्र, परिधान, चमड़ा, जूते, समुद्री उत्पाद, रत्न एवं आभूषण, हस्तशिल्प, इंजीनियरिंग वस्तुएँ और ऑटोमोबाइल जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों को निर्णायक प्रोत्साहन मिलेगा। लगभग 33 अरब अमेरिकी डॉलर के निर्यात पर 10% तक के शुल्क शून्य हो जाएंगे।

ऑटोमोबाइल क्षेत्र में चरणबद्ध एवं कोटा-आधारित उदारीकरण से "मेक इन इंडिया" और भविष्य के निर्यात को बल मिलेगा। भारतीय उपभोक्ताओं को उन्नत प्रौद्योगिकी और प्रतिस्पर्धा का लाभ प्राप्त होगा।

कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र—जैसे चाय, कॉफी, मसाले तथा फल एवं सब्जियों को प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिलेगी। साथ ही डेयरी, अनाज, पोल्ट्री आदि संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है।

सेवाओं में आईटी, पेशेवर सेवाएँ, शिक्षा, वित्तीय सेवाएँ, पर्यटन एवं निर्माण जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त होंगे। यूरोपीय संघ के 144 उप-क्षेत्रों में भारतीय सेवा प्रदाताओं को पूर्वानुमेय पहुँच मिलेगी। गतिशीलता प्रावधानों के अंतर्गत इंट्रा-कॉरपोरेट ट्रांसफरी (ICT), व्यवसायिक आगंतुकों तथा अनुबंधित सेवा प्रदाताओं के लिए सुगम व्यवस्था की गई है। सामाजिक सुरक्षा समझौतों एवं छात्र गतिशीलता के लिए भी ढाँचा तैयार किया गया है। भारतीय पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के विशेषज्ञों को भी अवसर प्रदान किए गए हैं।

बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में TRIPS प्रावधानों को सुदृढ़ करते हुए दोहा घोषणा की पुष्टि की गई है तथा भारत की पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी (TKDL) के महत्व को मान्यता दी गई है।

यह समझौता कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वच्छ प्रौद्योगिकी और सेमीकंडक्टर जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग को प्रोत्साहित करेगा।

भारत–ईयू एफटीए भारत की 22वीं एफटीए साझेदारी है। वर्ष 2014 के बाद भारत ने मॉरीशस, यूएई, यूके, ईएफटीए, ओमान और ऑस्ट्रेलिया सहित अनेक देशों के साथ व्यापार समझौते किए हैं।

यह समझौता "विकसित भारत 2047" के दृष्टिकोण के अनुरूप भारत को एक विश्वसनीय, गतिशील और भविष्य उन्मुख वैश्विक भागीदार के रूप में स्थापित करता है तथा समावेशी एवं सुदृढ़ विकास की आधारशिला रखता है।

मण्डल रेल प्रबंधक कार्यालय, अहमदाबाद में मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन

(जीएनएस)। कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य एवं समग्र कल्याण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पश्चिम रेलवे के मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) कार्यालय, अहमदाबाद में एक विशेष मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

मंडल रेल प्रबंधक, अहमदाबाद श्री वेद प्रकाश ने कार्यक्रम के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए बताया कि कर्मचारियों में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना, तनाव प्रबंधन के व्यावहारिक उपायों से परिचित कराना तथा स्वस्थ कार्य–जीवन संतुलन को बढ़ावा देना अत्यंत आवश्यक है।

इस कार्यक्रम में डॉ. मनोज कुमार देव अपर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (मनोचिकित्सा) ने प्रजेंटेशन के माध्यम से विस्तृत एवं ज्ञानवर्धक व्याख्यान दिया। उन्होंने बताया कि मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति अपने कार्य में अधिक दक्ष होने के साथ-साथ व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन में भी बेहतर संतुलन बनाए रखता है। उन्होंने अवसाद, चिंता, कार्यस्थल तनाव एवं भावनात्मक थकान जैसी सामान्य मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं की पहचान, उनके प्रारंभिक लक्षणों तथा समय पर उपचार की आवश्यकता पर विस्तार से जानकारी दी। डॉ. देव ने मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर खुलकर चर्चा करने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि सहायता लेने में किसी प्रकार का संकोच नहीं होना चाहिए। उन्होंने सामाजिक कलंक (स्टिग्मा) को दूर करने पर जोर देते हुए मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और उपचार को शारीरिक रोगों के उपचार जितना ही महत्वपूर्ण बताया। साथ ही कर्मचारियों को नियमित व्यायाम, संतुलित आहार, पर्याप्त विश्राम, सकारात्मक सोच एवं संवाद को जीवनशैली का हिस्सा बनाने की सलाह दी। इस अवसर पर उपस्थित मंडल रेल प्रबंधक श्री वेद प्रकाश ने कर्मचारियों के कल्याण के प्रति रेलवे प्रशासन की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि स्वस्थ एवं संतुलित मनोस्थिति ही उत्कृष्ट कार्य निष्पादन का आधार है। उन्होंने अधिकारियों एवं पर्यवेक्षकों को अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की मानसिक स्थिति के प्रति संवेदनशील रहने तथा आवश्यकता पड़ने पर विशेषज्ञ चिकित्सकीय परामर्श उपलब्ध कराने पर बल दिया। प्रेरक उदाहरणों के माध्यम से उन्होंने सकारात्मक सोच, संवाद एवं सहयोगात्मक कार्य संस्कृति को अपनाने के लिए प्रेरित किया।

कार्यक्रम के दौरान आयोजित प्रश्नोत्तर सत्र में कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए मानसिक तनाव, कार्यस्थल दबाव, पारिवारिक–व्यावसायिक संतुलन एवं परामर्श सेवाओं से संबंधित प्रश्न पूछे। विशेषज्ञ द्वारा दिए गए व्यावहारिक सुझावों को प्रतिभागियों ने उपयोगी एवं मार्गदर्शक बताया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोको निरीक्षक, कल्याण निरीक्षक तथा विभिन्न विभागों के कर्मचारी उपस्थित रहे। पश्चिम रेलवे द्वारा इस प्रकार के कार्यक्रम कर्मचारियों के समग्र विकास, सकारात्मक कार्य वातावरण एवं स्वस्थ कार्य संस्कृति को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल हैं। रेलवे प्रशासन भविष्य में भी ऐसे आयोजनों के माध्यम से कर्मचारियों के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देता है।

आईटी और बैंकिंग शेयरों की मजबूती से बाजार में लौटा विश्वास

(जीएनएस)। नई दिल्ली। भारतीय शेयर बाजार ने सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन भी मजबूती का प्रदर्शन करते हुए लगातार दूसरे दिन बढ़त के साथ कारोबार समाप्त किया। निवेशकों के सकारात्मक रुख और प्रमुख क्षेत्रों में खरीदारी के कारण बाजार में उत्साह का माहौल बना रहा। विशेष रूप से बैंकिंग, सूचना प्रौद्योगिकी और पूंजीगत वस्तुओं से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में आई तेजी ने बाजार को मजबूती प्रदान की और प्रमुख सूचकांकों को ऊंचे स्तर पर बंद होने में मदद की। यह लगातार दूसरा दिन रहा जब बाजार ने सकारात्मक संकेत दिए और निवेशकों के भरोसे को मजबूत किया।

कारोबार के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 173.81 अंकों की बढ़त के साथ 83,450.96 के स्तर पर बंद हुआ। दिन के दौरान सेंसेक्स ने 83,598 का उच्चतम और 82,987.43 का न्यूनतम स्तर छुआ, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि बाजार में उतार-चढ़ाव के बावजूद निवेशकों का भरोसा बना हुआ है। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख सूचकांक निफ्टी 42.65 अंकों की बढ़त के साथ 25,725.40 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी की यह बढ़त इस बात का संकेत है कि व्यापक स्तर पर बाजार में खरीदारी का रुझान बना रहा और निवेशकों ने प्रमुख कंपनियों में निवेश जारी रखा।

विशेषज्ञों का मानना है कि बाजार की इस तेजी के पीछे कई महत्वपूर्ण कारण हैं, जिनमें सबसे प्रमुख बैंकिंग और आईटी सेक्टर में निवेशकों की सक्रियता रही। बैंकिंग शेयरों में खरीदारी से बाजार को मजबूत आधार मिला, क्योंकि बैंकिंग क्षेत्र को अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है।

जीवंत विरासत का शहर वडनगर बना संतुलित विकास का आदर्श मॉडल

▸▸ शहरी विकास और शहरी गृह निर्माण विभाग की अधीनस्थ गुजरात शहरी विकास कंपनी के अंतर्गत ऐतिहासिक स्थलों का जीर्णोद्धार, सड़कों का विकास और तालाबों को आपस में जोड़ने जैसे विकास कार्य किए जाएंगे
▸▸ गायों के संरक्षण के लिए बनेगी देश की पहली भव्य वृंदावन गौशाला, जो ग्रामीण गौशाला विकास का बनेगी एक आदर्श मॉडल
▸▸ विद्युत विभाग के अंतर्गत भूमिगत विद्युतीकरण और सौरकरण के जरिए वडनगर का होगा कायापलट

(जीएनएस)। गांधीनगर : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'विकास भी, विरासत भी' के विजन को ध्यान में रखते हुए गुजरात सरकार राज्य में ऐतिहासिक विरासत के संरक्षण के साथ-साथ इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का संतुलित मॉडल विकसित कर रही है। इसकी शानदार मिसाल है ऐतिहासिक शहर वडनगर। पुरातत्व, संस्कृति और इतिहास का जीवंत उदाहरण बन चुका वडनगर शहर लगभग 2500 साल पुराने सांस्कृतिक इतिहास को अपने में समेटे हुए है। पुरातात्विक अनुभवात्मक संग्रहालय का निर्माण हो या निर्माणाधीन देश की पहली भव्य वृंदावन गौशाला या फिर ऐतिहासिक स्थलों का जीर्णोद्धार कार्य, गुजरात सरकार के निरंतर प्रयासों के कारण वडनगर आज एक टिकाऊ शहरी मॉडल के रूप में विकसित हो रहा है।

पुरातात्विक अनुभवात्मक संग्रहालय, प्रेरणा संकुल और आधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स

वडनगर के 2500 साल पुराने गौरवशाली इतिहास को संरक्षित करने के लिए गत वर्ष पुरातात्विक अनुभवात्मक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया था। 300 करोड़ रुपए की लागत से तैयार यह संग्रहालय भारत का एकमात्र ऐसा संग्रहालय है, जो नए उत्खनन कार्यों से मिली वस्तुओं को प्रदर्शित करता है। संग्रहालय में 5 हजार से अधिक कलाकृतियां प्रदर्शित की गई हैं। इतना ही नहीं, 9 विषयगत दीर्घाएं भी बनाई गई हैं, जो विभिन्न कालखंडों की कलाओं, शिल्पों और विभिन्न भाषाओं को प्रदर्शित करती हैं।

वहीं, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जिस स्कूल में अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी, उस प्रेरणा स्कूल (संकुल) को भविष्य के आधुनिक शैक्षणिक संस्थान के रूप में विकसित किया गया है, जिसमें नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से शिक्षा और नैतिक मूल्यों का अनूठा संगम है। यह दुनिया का पहला अनुभवात्मक ज्ञान-आधारित शिक्षा केंद्र है। इसके अलावा, वडनगर में अत्याधुनिक सुविधाओं वाले स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भी निर्माण किया गया है, जिसमें छात्रावास, कोच ऑफिस, रेक्टर क्वार्टर, आधुनिक रसोई घर, डाइनिंग रूम और रिक्रिएशन रूम जैसी सुविधाएं और सोलर सिस्टम एवं सीसीटीवी कैमरों जैसी आधुनिक सुविधाएं भी शामिल हैं।

विश्व स्तरीय हेरिटेज-टूरिज्म डेस्टिनेशन बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है वडनगर

वडनगर में कीर्ति तोरण, शर्मिष्ठा तालाब, प्राचीन दरवाजों और किले की दीवारों (परकोटे) के अवशेष, हाटकेश्वर महादेव मंदिर और आसपास का क्षेत्र, बौद्ध मठ के पुरातात्विक अवशेष और ताना-रीरी स्मारक जैसे स्थलों के जीर्णोद्धार से शहर की समृद्ध विरासत जीवंत बन गई है। ऐतिहासिक विरासत के संरक्षण के साथ-साथ शहर के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देने के गुजरात सरकार के दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप वडनगर आज एक विश्व स्तरीय हेरिटेज-टूरिज्म डेस्टिनेशन बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

उल्लेखनीय है कि वडनगर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है, जिसके अंतर्गत नॉमिनेशन डॉजियर और साइट मैनेजमेंट प्लान तैयार कर लिया गया है। इन विकास कार्यों से वडनगर का होगा कायापलट

भव्य वृंदावन गौशाला : 15 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से देश की पहली भव्य 'वृंदावन गौशाला' का निर्माण किया जाएगा। गौशाला को 'रूरल इनोवेशन हब' के रूप में विकसित किया जाएगा और यह गायों के संरक्षण के लिए ग्रामीण गौशाला विकास का एक आदर्श मॉडल बनेगी।

तालाबों और जलाशयों को आपस में जोड़ने का प्रोजेक्ट : वडनगर में 40 से अधिक तालाबों को आपस में जोड़कर पानी को सहेजने और उसकी निकासी की व्यवस्था की जाएगी। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत तालाबों को गहरा और सुव्यवस्थित बनाकर उनका सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, प्राकृतिक ग्रेविटी फ्लो सिस्टम लागू किया जाएगा, जिससे शहर के बरसाती पानी की निकासी की व्यवस्था सुदृढ़ होगी।

▸▸ पुरातात्विक अनुभवात्मक संग्रहालय में नजर आता है वडनगर का 2500 साल पुराना गौरवशाली इतिहास, प्रेरणा संकुल बना दुनिया का पहला अनुभवात्मक ज्ञान-आधारित शिक्षा केंद्र

हेरिटेज परिसर और फसाद डेवलपमेंट : प्रेरणा स्कूल परिसर, कीर्ति तोरण परिसर, पत्थर की हवेली और शर्मिष्ठा तालाब के आसपास के इलाकों में पारंपरिक स्थापत्य को संरक्षित रखते हुए फसाद (ऐतिहासिक इमारतों आदि का अग्रभाग) और हेरिटेज परिसर विकास के काम शुरू किए गए हैं, जिससे ऐतिहासिक इलाकों के सौंदर्य को चार चांद लग जाएंगे।

हेरिटेज रोड और जंक्शन विकास (फेज-2) : शहर की मुख्य सड़कों और जंक्शनों को हेरिटेज थीम के आधार पर विकसित किया जाएगा, जिससे यातायात प्रबंधन में सुधार के साथ ही पर्यटकों को सहज एवं बेहतर अनुभव मिलेगा।

भूमिगत विद्युतीकरण और सौरकरण : शहर में ओवरहेड विद्युत लाइनों को भूमिगत नेटवर्क में रूपांतरित किया जा रहा है। साथ ही, घरों और सरकारी इमारतों पर सोलर पैनल लगाकर वडनगर को ऊर्जा की दृष्टि से और अधिक टिकाऊ बनाने की दिशा में काम चल रहा है।

योजनाबद्ध पुनर्वास और स्लम रीडेवलपमेंट : योजनाबद्ध पुनर्वास कार्यों और स्लम रीडेवलपमेंट (झुग्गियों का पुनर्विकास) योजना के माध्यम से शहरी जीवन में सुधार लाया जाएगा।

नए अंदाज़ में उपभोक्ताओं के सामने आएगा Lay's, बदलेगा पैकेट का रूप और ब्रांड की पहचान

(जीएनएस)। नई दिल्ली। वैश्विक स्नैक फूड उद्योग में अपनी मजबूत पहचान रखने वाली PepsiCo ने अपने लोकप्रिय आलू चिप्स ब्रांड Lay's को नए लुक और नई ब्रांड पहचान के साथ भारत में पेश करने का निर्णय लिया है। कंपनी ने घोषणा की है कि मार्च के पहले सप्ताह से भारतीय बाजार में Lay's के चिप्स नए लोगो और आकर्षक पैकेजिंग डिज़ाइन के साथ उपलब्ध होंगे। यह बदलाव केवल एक साधारण पैकेजिंग परिवर्तन नहीं है, बल्कि यह कंपनी के लगभग एक सदी पुराने ब्रांड इतिहास में सबसे बड़ा वैश्विक रीब्रांडिंग अभियान माना जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य ब्रांड को आधुनिक, युवा और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अधिक प्रभावशाली स्वरूप देना है। कंपनी के अनुसार, Lay's की नई पैकेजिंग को विशेष रूप से इस तरह तैयार किया गया है, जिससे उपभोक्ताओं को ब्रांड की ताजगी, गुणवत्ता और विश्वसनीयता का अनुभव पहले से अधिक स्पष्ट रूप से हो सके। नए डिज़ाइन में अधिक चमकीले रंग, आधुनिक ग्राफिक्स और बेहतर दृश्य संतुलन का उपयोग किया गया है, जिससे पैकेट न केवल आकर्षक दिखेगा, बल्कि स्टोर की शेल्फ पर आसानी से पहचाना भी जा सकेगा। यह बदलाव उपभोक्ताओं की बदलती पसंद और आधुनिक बाजार की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किया गया है। PepsiCo ने स्पष्ट किया है कि यह रीब्रांडिंग अभियान केवल भारत तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसे दुनिया के कई प्रमुख बाजारों में लागू किया जा रहा है। कंपनी का लक्ष्य अपने ब्रांड की वैश्विक पहचान को एक समान और मजबूत बनाना है, ताकि चाहे उपभोक्ता किसी भी देश में Lay's का पैकेट देखें, उन्हें एक समान अनुभव और पहचान महसूस हो। इस वैश्विक रणनीति के माध्यम से PepsiCo अपने ब्रांड को और अधिक संगठित और प्रतिस्पर्धात्मक बनाना चाहती है। भारत जैसे बड़े और तेजी से बढ़ते बाजार में Lay's पहले से ही स्नैक फूड श्रेणी में एक प्रमुख नाम है। वर्षों से यह ब्रांड बच्चों, युवाओं और परिवारों के बीच लोकप्रिय बना हुआ है। ऐसे में नई पैकेजिंग के माध्यम से कंपनी न केवल अपने मौजूदा ग्राहकों को आकर्षित बनाए रखना चाहती है, बल्कि नए उपभोक्ताओं को भी जोड़ने का प्रयास कर रही है।

पश्चिम रेलवे द्वारा स्पेशल ट्रेनों के फेरे बढ़ाए जाएगे

ट्रेन क्र.	प्रस्थान स्टेशन और गंतव्य	सेवा के दिन	से विस्तृत
09465	अहमदाबाद – दरभंगा	शुक्रवार	27.03.2026
09466	दरभंगा - अहमदाबाद	सोमवार	30.03.2026
09447	अहमदाबाद – पटना	बुधवार	25.03.2026
09448	पटना - अहमदाबाद	शुक्रवार	27.03.2026

समय, ठहराव और संरचना के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए, यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जा सकते हैं।

ट्रेन नंबर 09465 और 09447 के बढ़े हुए ट्रिप के लिए बुकिंग 18.02.2026 से सभी PRS काउंटर और IRCTC वेबसाइट पर शुरू होगी। ऊपर बताई गई ट्रेनें स्पेशल ट्रेन के तौर पर स्पेशल किराए पर चलाई जाएगी।

पश्चिम रेलवे
wr.indianrailways.gov.in
हमें लाइक करें और फॉलो करें:
facebook.com/WesternRly
X.com/WesternRly
Instagram.com/WesternRly
https://www.youtube.com/@WesternRly
https://bit.ly/WesternRailwayOfficial

कृपया सभी आरक्षित टिकटों के लिए मूल पहचान पत्र साथ रखें।

भारत और फ्रांस की रणनीतिक साझेदारी का नया स्वर्णिम अध्याय

(जीएनएस)। भारत और फ्रांस के बीच संबंधों ने एक बार फिर इतिहास रचते हुए वैश्विक मंच पर एक नई मिसाल कायम की है। मुंबई में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के बीच हुई वार्ता ने दोनों देशों की दोस्ती को अभूतपूर्व ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। इस ऐतिहासिक मुलाकात में कुल 21 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए, जो रक्षा, अंतरिक्ष, ऊर्जा, तकनीक, स्वास्थ्य, नवाचार और औद्योगिक सहयोग जैसे अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों को कवर करते हैं। यह समझौते केवल वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नहीं हैं, बल्कि आने वाले कई दशकों के लिए एक मजबूत और दूरदर्शी साझेदारी का आधार तैयार करते हैं।

भारत और फ्रांस के संबंध हमेशा से विश्वास, सम्मान और साझा मूल्यों पर आधारित रहे हैं। दोनों देश लोकतंत्र, स्वतंत्रता, बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था और वैश्विक शांति के समर्थक रहे हैं। यही कारण है कि जब विश्व में कई देशों के बीच संबंध अस्थिर होते दिखाई देते हैं, तब भारत और फ्रांस की मित्रता लगातार मजबूत होती जा रही है। इस बार दोनों देशों ने अपने संबंधों को "स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप" का दर्जा देकर यह स्पष्ट कर दिया है कि यह साझेदारी केवल औपचारिक नहीं, बल्कि एक दीर्घकालिक रणनीतिक सहयोग है।

इस बैठक का सबसे महत्वपूर्ण पहलू रक्षा क्षेत्र में सहयोग का विस्तार रहा है। दोनों देशों ने रक्षा सहयोग समझौते को नवीनीकृत किया है और आधुनिक सैन्य तकनीक के संयुक्त विकास पर सहमति जताई है। विशेष रूप से, Safran और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बीच HAMMER मिसाइल उत्पादन के लिए संयुक्त उद्यम स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। यह कदम भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे भारत न केवल अपनी सैन्य जरूरतों को पूरा कर सकेगा, बल्कि भविष्य में रक्षा उपकरणों का निर्यात भी कर सकेगा।

इसके अलावा, भारतीय सेना और फ्रेंच लैंड फोर्सेस के बीच अधिकारियों की परस्पर तैनाती पर भी सहमति बनी है। यह कदम दोनों देशों की सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल और प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करेगा। इससे दोनों देशों की सैन्य क्षमता और सामरिक समझ में वृद्धि होगी, जो भविष्य में किसी भी वैश्विक चुनौती का सामना करने में सहायक सिद्ध होगी।

इस ऐतिहासिक सहयोग का एक और महत्वपूर्ण पहलू हेलीकॉप्टर निर्माण परियोजना है। Airbus और टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड के संयुक्त सहयोग से कर्नाटक के वेमगल में हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र स्थापित किया गया है। इस संयंत्र में H125 हेलीकॉप्टर का निर्माण किया जाएगा, जो दुनिया के सबसे सक्षम और भरोसेमंद हेलीकॉप्टरों में से एक माना जाता है। यह वही हेलीकॉप्टर है जो माउंट एवरेस्ट जैसी ऊंची और चुनौतीपूर्ण जगहों पर भी सफलतापूर्वक उड़ान भर सकता है। इस परियोजना का महत्व केवल तकनीकी दृष्टि से ही नहीं, बल्कि आर्थिक और औद्योगिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस संयंत्र में प्रतिवर्ष 10 नागरिक हेलीकॉप्टरों का निर्माण किया जाएगा और आने वाले 20 वर्षों में कुल 500 हेलीकॉप्टर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इससे भारत में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और देश की औद्योगिक क्षमता में वृद्धि होगी। साथ ही, यह परियोजना भारत को वैश्विक हेलीकॉप्टर निर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने में भी मदद करेगी।

भारत और फ्रांस न केवल रक्षा और औद्योगिक क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि नवाचार और तकनीक के क्षेत्र में भी सहयोग को मजबूत करने का निर्णय लिया है। दोनों देशों ने "इंडिया-फ्रांस इनोवेशन नेटवर्क" की स्थापना पर सहमति जताई है, जिसका उद्देश्य नई तकनीकों का विकास और स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देना है। यह नेटवर्क कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर सुरक्षा, डिजिटल तकनीक और वैज्ञानिक अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देगा।

स्वास्थ्य क्षेत्र में भी दोनों देशों ने संयुक्त अनुसंधान केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है, जहां मेटाबोलिक स्वास्थ्य और हेल्थ AI पर शोध किया जाएगा। यह सहयोग भविष्य में नई चिकित्सा तकनीकों और उपचार पद्धतियों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इससे दोनों देशों के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

ऊर्जा क्षेत्र में भी भारत और फ्रांस ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं पर सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया है। दोनों देश सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और हरित हाइड्रोजन जैसे क्षेत्रों में संयुक्त निवेश करेंगे। यह कदम जलवायु परिवर्तन से निपटने और पर्यावरण संरक्षण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे न केवल ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित होगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा।

इस साझेदारी का एक और महत्वपूर्ण पहलू अंतरिक्ष सहयोग है। भारत और फ्रांस पहले से ही अंतरिक्ष अनुसंधान में सहयोग कर रहे हैं, लेकिन अब इस सहयोग को और अधिक व्यापक बनाने का निर्णय लिया गया है। दोनों देश उपग्रह प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष मिशनों और अंतरिक्ष सुरक्षा के क्षेत्र में संयुक्त रूप से काम करेंगे। इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में नई संभावनाएं खुलेंगी और वैश्विक स्तर पर दोनों देशों की स्थिति मजबूत होगी।

इस ऐतिहासिक बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त रूप से लड़ने की प्रतिबद्धता दोहराई और कहा कि आतंकवाद किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। दोनों देशों ने यूक्रेन, पश्चिम एशिया और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के प्रयासों का समर्थन करने का भी निर्णय लिया।

यह साझेदारी भारत के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह देश को वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग और तकनीकी केंद्र बनने की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेगी। फ्रांस जैसी तकनीकी रूप से उन्नत और औद्योगिक रूप से मजबूत देश के साथ सहयोग से भारत को नई तकनीकों तक पहुंच मिलेगी और देश की औद्योगिक क्षमता में वृद्धि होगी।

फ्रांस के लिए भी यह साझेदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। भारत के विशाल बाजार और युवा जनसंख्या फ्रांस के लिए नए अवसर प्रदान करते हैं। दोनों देशों के बीच बढ़ता व्यापार और निवेश दोनों देशों की अर्थव्यवस्था के लिए लाभकारी सिद्ध होगा।

यह ऐतिहासिक समझौते यह स्पष्ट करते हैं कि भारत और फ्रांस की मित्रता केवल वर्तमान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भविष्य की संभावनाओं से भी परिपूर्ण है। यह साझेदारी दोनों देशों के विकास, सुरक्षा और समृद्धि के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करेगी। आने वाले वर्षों में यह सहयोग और भी मजबूत होगा और दोनों देश मिलकर वैश्विक मंच पर नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। भारत और फ्रांस की यह मित्रता केवल दो देशों के बीच संबंधों का उदाहरण नहीं है, बल्कि यह वैश्विक सहयोग और साझेदारी का एक आदर्श मॉडल भी है। यह दिखाता है कि जब दो देश साझा मूल्यों और लक्ष्यों के साथ मिलकर काम करते हैं, तो वे न केवल अपने नागरिकों के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं, बल्कि पूरे विश्व के लिए शांति, स्थिरता और विकास का मार्ग भी प्रशस्त कर सकते हैं।

आत्मनिर्भर गांव ही बनेंगे विकसित भारत की असली ताकत 12% GDP ग्रोथ का रास्ता ग्रामीण क्रांति से होकर गुजरेगा

(जीएनएस)। सूरत में आयोजित एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस में देश के आर्थिक भविष्य, ग्रामीण विकास और 'विकसित भारत @2047' के विजन को लेकर एक नई और प्रेरणादायक दिशा सामने आई। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर से शिक्षित और भारत सरकार की पूर्व सलाहकार विप्रा गोयल ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए केवल शहरी विकास पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसके लिए गांवों को आत्मनिर्भर बनाना सबसे आवश्यक और निर्णायक कदम होगा। उन्होंने कहा कि यदि भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करना है, तो देश को कम से कम 12 प्रतिशत की वार्षिक GDP वृद्धि दर हासिल करनी होगी, और यह लक्ष्य तभी संभव है जब ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत, टिकाऊ और आत्मनिर्भर बने।

उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि भारत की असली शक्ति उसके गांवों में बसती है, जहां देश की बड़ी आबादी रहती है और जहां से कृषि, श्रम और उत्पादन की नींव तैयार होती है। यदि गांव आर्थिक रूप से मजबूत होंगे, तो इसका सीधा असर पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। उन्होंने बताया कि देश के लगभग 10 करोड़ किसान परिवार आज भी सीमित आय पर निर्भर हैं, लेकिन यदि सरकार की योजनाओं को सही तरीके से लागू किया जाए और किसानों को आधुनिक संसाधन उपलब्ध कराए जाएं, तो उनकी वार्षिक आय 24,000 रुपये से बढ़कर 1.5 लाख से 2 लाख रुपये तक पहुंच सकती है। यह वृद्धि केवल किसानों के जीवन स्तर को बेहतर नहीं बनाएगी, बल्कि पूरे देश में उपभोक्ता मांग को भी बढ़ाएगी।

उन्होंने समझाया कि जब गांवों में आय बढ़ती है, तो लोग अधिक कपड़े, घरेलू सामान, कृषि उपकरण और अन्य उपभोक्ता वस्तुएं खरीदते हैं। इसका सीधा लाभ देश के लगभग 9 करोड़ लघु उद्योगों को मिलता है। इससे रोजगार बढ़ता है, उत्पादन बढ़ता है और अर्थव्यवस्था में तेजी आती है। इस प्रकार ग्रामीण समृद्धि शहरी औद्योगिक विकास को भी गति देती है और दोनों के बीच एक मजबूत आर्थिक चक्र स्थापित होता है।

उन्होंने विशेष रूप से जल संकट और भूजल के लगातार गिरते स्तर को देश के लिए गंभीर खतरा बताया। उन्होंने कहा कि यदि भूजल दोहन को नियंत्रित नहीं किया गया, तो आने वाले वर्षों में खेती की जमीन बंजर हो सकती है और खाद्य सुरक्षा पर संकट आ सकता है। उन्होंने इसका व्यावहारिक समाधान बताते हुए कहा कि यदि किसान अपनी जमीन के केवल 5 प्रतिशत हिस्से में खेत तालाब या फार्म पॉन्ड बनाएं, तो वर्ष भर सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध हो सकता है। यह एक सरल लेकिन अत्यंत प्रभावी उपाय है, जिससे किसान बारिश के पानी को संरक्षित कर सकते हैं और सूखे के समय भी खेती जारी रख सकते हैं।

इसके साथ ही उन्होंने ऊर्जा आत्मनिर्भरता पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि यदि किसान अपनी जमीन के केवल 1 प्रतिशत हिस्से में सोलर पैनल लगाएं, तो वे अपनी बिजली की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं और अतिरिक्त बिजली बेचकर आय भी अर्जित कर सकते हैं। इससे न केवल किसानों की आय बढ़ेगी, बल्कि देश की ऊर्जा आत्मनिर्भरता भी मजबूत होगी और पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी।

उन्होंने यह भी बताया कि सरकार द्वारा चलाई जा रही कई महत्वपूर्ण योजनाएं, जैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, अटल भूजल योजना और प्रधानमंत्री कुसुम योजना, ग्रामीण विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। लेकिन इन योजनाओं का पूरा लाभ तभी मिल सकता है जब गांवों के लोगों को इनके बारे में सही जानकारी और जागरूकता हो। उन्होंने कहा कि देश के लगभग 80 करोड़ ग्रामीण नागरिकों तक इन योजनाओं की जानकारी पहुंचाने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का जागरूकता अभियान शुरू किया जा रहा है।

उन्होंने सूरत की अर्थव्यवस्था और ग्रामीण विकास के बीच के गहरे संबंध को भी स्पष्ट किया। उन्होंने बताया कि सूरत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री की लगभग 60 प्रतिशत मांग ग्रामीण क्षेत्रों से आती है।

सूरत नगर निगम का 11,301 करोड़ का ऐतिहासिक बजट पारित, विकास और तकनीकी प्रगति का नया विजन

(जीएनएस)। सूरत शहर के विकास, आधुनिक बुनियादी ढांचे और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सूरत नगर निगम ने 11,301 करोड़ रुपये का विशाल और महत्वाकांक्षी बजट पारित कर दिया है। यह बजट दो दिनों तक चली विस्तृत और मैराथन चर्चा के बाद जनरल मीटिंग में मंजूर किया गया, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के कुल 82 नगर सेवकों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। इस दौरान करीब 1020 मिनट तक चर्चा चली, जिसमें शहर के विकास, नागरिक सुविधाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य, तकनीक और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से विचार-विमर्श हुआ। अंततः स्थायी समिति अध्यक्ष, उप महापौर, नगर आयुक्त और महापौर के संबोधन के बाद इस बजट को पारित कर राज्य सरकार को मंजूरी के लिए भेज दिया गया। इस बजट की सबसे खास बात यह रही कि बिना किसी नए टैक्स के शहर के व्यापक विकास की योजना तैयार की गई है। यह लगातार तीसरा ऐसा बजट है जिसे 'रेवेन्यू सरप्लस' बजट के रूप में पेश किया गया है। इसका मतलब यह है कि नगर निगम अपनी आय और खर्च के बीच संतुलन बनाते हुए शहर के विकास कार्यों को आगे बढ़ा रहा है, जिससे नागरिकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा। यह मॉडल न केवल वित्तीय अनुशासन को दर्शाता है, बल्कि नगर प्रशासन की दूरदर्शिता और कुशल प्रबंधन का भी प्रतीक है।

महापौर दक्षेश मावाणी ने बजट चर्चा के समापन पर कहा कि सूरत का विकास पिछले तीन दशकों में अभूतपूर्व रहा है। उन्होंने बताया कि वर्ष 1995 में सूरत नगर निगम का बजट मात्र 240 करोड़ रुपये का था, जो अब बढ़कर 11,301 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। यह वृद्धि लगभग 47 गुना है, जो शहर की आर्थिक मजबूती और तेज विकास को दर्शाती है। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले समय में बुलेट ट्रेन परियोजना के शुरू होने से सूरत को और अधिक लाभ मिलेगा, जिससे शहर से मुंबई की दूरी केवल एक घंटे की रह जाएगी और सूरत वैश्विक स्तर पर और अधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक और

औद्योगिक केंद्र के रूप में उभरेगा। स्थायी समिति के अध्यक्ष राजन पटेल ने बजट को 'डेवलप्ड इंडिया @2047' के विजन के अनुरूप बताया। उन्होंने कहा कि इस बजट में शिक्षा, युवा विकास, स्वास्थ्य, पर्यावरण और तकनीकी प्रगति को विशेष प्राथमिकता दी गई है। नगर प्राथमिक शिक्षा समिति के लिए 1062.93 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत छात्रों को आधुनिक सुविधाएं जैसे स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म, एआर/वीआर लैब, 7D लैब और आधुनिक पुस्तकालय उपलब्ध कराए जाएंगे। इन सुविधाओं का उद्देश्य छात्रों को भविष्य की तकनीकी चुनौतियों के लिए तैयार करना और उन्हें वैश्विक स्तर की शिक्षा प्रदान करना है।

तकनीकी विकास के क्षेत्र में सूरत नगर निगम ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 10 करोड़ रुपये की लागत से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही अंतरराष्ट्रीय स्तर का STEM और रोबोटिक्स ओलंपियाड आयोजित करने की योजना बनाई गई है, जिससे छात्रों को विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। यह पहल सूरत को देश के अग्रणी तकनीकी शहरों में शामिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में भी बजट में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। गंगा स्वरूपा (विधवा) महिलाओं को प्रॉपर्टी टैक्स में पूर्ण छूट देने का निर्णय लिया गया है, जिससे उन्हें आर्थिक राहत मिलेगी। इसके अलावा 'सूरती हाट' में मुफ्त दुकानें उपलब्ध कराकर स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। यह कदम सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाया गया है।

स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए 'टीबी फ्री सूरत' अभियान और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 'वदिल वंदना योजना' शुरू की गई है। इसके तहत वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य जांच और बीआरटीएस में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी। यह पहल बुजुर्गों के स्वास्थ्य और सम्मान को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।

इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के क्षेत्र में भी बजट में कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। शहर में आरसीसी सड़कों का निर्माण, जल संरक्षण के लिए रिचार्ज बोरवेल और नेचर पार्कों के आधुनिकीकरण के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह कदम न केवल शहर की आधारभूत संरचना को मजबूत करेगा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

उप महापौर डॉ. नरेंद्र पाटिल ने बजट को संतुलित और समावेशी विकास का उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि इस बजट में लिंबायत क्षेत्र के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को शामिल किया गया है। क्षेत्र में चार नए स्कूलों के निर्माण, नए स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना और अत्याधुनिक ऑडिटोरियम के निर्माण का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा नई ड्रेनेज लाइन, पानी की पाइपलाइन और सीसी सड़कों के निर्माण से क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाएगा। उन्होंने बताया कि लिंबायत क्षेत्र की 200 सोसायटियों में से 140 में सीसी सड़कें बनाई जा चुकी हैं और 1.05 लाख की आबादी के लिए तीन स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए गए हैं। यह विकास कार्य क्षेत्र के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

नगर आयुक्त एम. नागराजन ने कहा कि नगर निगम का लक्ष्य सूरत को विश्व स्तरीय शहर बनाना है।

अहमदाबाद-दरभंगा और अहमदाबाद–पटना स्पेशल ट्रेनों के फेरे विस्तारित

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे द्वारा आगामी होली त्योहार के दौरान यात्रियों की सुविधा तथा अतिरिक्त भीड़ को समायोजित करने के उद्देश्य से अहमदाबाद-दरभंगा और अहमदाबाद–पटना के बीच चल रही विशेष ट्रेनों के फेरों को विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है।इन ट्रेनों का विवरण निम्नानुसार है : ट्रेन संख्या 09465 अहमदाबाद - दरभंगा स्पेशल को 27 मार्च, 2026 तक विस्तारित किया गया है। ट्रेन संख्या 09447 अहमदाबाद - पटना स्पेशल को 25 मार्च, 2026 तक विस्तारित किया गया है।

ट्रेन संख्या 09465 तथा 09447 के विस्तारित फेरों की बुकिंग 18.02.2026 से सभी पीआरएस काउंटरों तथा आईआरसीटीसी वेबसाइट पर शुरू होगी। ट्रेनों के ठहराव, संरचना एवं समय के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

महिलाओं की आर्थिक सशक्तता की दिशा में मजबूत कदम: आटकोट में सखी मंडलों को मिली नई ऊर्जा

(जीएनएस)। गांवों की वास्तविक शक्ति वहां की महिलाएं होती हैं, जो अपने श्रम, धैर्य और समर्पण से न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे समाज की आर्थिक और सामाजिक संरचना को मजबूत बनाती हैं। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए कुंवरजीभाई बावलिया, जो गुजरात सरकार में श्रम, कौशल विकास, रोजगार एवं ग्रामीण विकास मंत्री हैं, ने राजकोट जिले के जसदण तालुका के आटकोट गांव में सखी मंडलों को लाखों रुपये की ऋण सहायता प्रदान कर ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। यह कार्यक्रम न केवल वित्तीय सहायता वितरण का अवसर था, बल्कि ग्रामीण महिलाओं की उपलब्धियों को सम्मानित करने और उनके आत्मविश्वास को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का भी एक प्रेरणादायक मंच बना। आटकोट गांव में आयोजित 'आटकोट क्लस्टर ले फेडरेशन' की वार्षिक आम बैठक में बड़ी संख्या में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं, पंचायत प्रतिनिधि, अधिकारी और स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ पारंपरिक दीप प्रज्वलन के साथ हुआ, जो ज्ञान, ऊर्जा और सकारात्मक परिवर्तन का प्रतीक माना जाता है। इस अवसर पर समुदाय की ओर से मंत्री कुंवरजीभाई बावलिया का भव्य स्वागत किया गया, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि ग्रामीण जनता अपने नेतृत्व से कितनी आशाएं और अपेक्षाएं रखती है। स्वागत समारोह के दौरान विवेकानंद स्कूल की छात्राओं द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक नृत्य ने कार्यक्रम को और अधिक जीवंत और प्रेरणादायक बना दिया। यह आयोजन राजकोट जिला ग्रामीण विकास एजेंसी और जसदण तालुका पंचायत कार्यालय के संयुक्त प्रयासों से आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में अधिकारियों ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत चल रही योजनाओं की जानकारी दी और बताया कि किस प्रकार ये योजनाएं ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में सहायक हो रही हैं। स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं ने भी अपने अनुभव साझा किए और बताया कि किस प्रकार सखी मंडलों से जुड़कर उन्होंने आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त की और अपने परिवार की स्थिति को बेहतर बनाया।

इस अवसर पर विभिन्न सखी मंडलों और क्लस्टर संगठनों को महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान की गई। 'चामुंडा मिशन मंगलम, अटकोट' को 3 लाख रुपये, 'गोपाल मिशन मंगलम, गुंडलाजम' को 1.5 लाख रुपये, क्लस्टर स्तरीय महासंघ अटकोट को 4.5 लाख रुपये और बैंक ऑफ इंडिया, अटकोट को 2.5 लाख रुपये की सहायता प्रदान की गई। इसके साथ ही 80,552 रुपये की ब्याज सब्सिडी भी वितरित की गई, जिससे सखी मंडलों की आर्थिक गतिविधियों को और अधिक गति मिलेगी। यह वित्तीय सहायता केवल धनराशि नहीं है, बल्कि यह महिलाओं के आत्मविश्वास, उनके सपनों और उनकी क्षमताओं में सरकार के विश्वास का प्रतीक है। कार्यक्रम के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित भी किया गया।

सोना-चांदी के वायदाओं में गिरावट जारी: सोना वायदा 1.51 लाख रुपये और चांदी वायदा 2.29 लाख रुपये के स्तर पर पहुँचा

(जीएनएस)। मुंबईः देश के अग्रणी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स में 256200.49 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदाओं में 27646.12 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कमोडिटी ऑप्शंस में 228553.48 करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स का फरवरी वायदा 37388 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था। कमोडिटी ऑप्शंस में कुल प्रीमियम टर्नओवर 2688.37 करोड़ रुपये का हुआ।

कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 20618.94 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना अप्रैल वायदा 153551 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 153959 रुपये और नीचे में 151244 रुपये पर पहुंचकर, 154760 रुपये के पिछले बंद के सामने 1802 रुपये या 1.16 फीसदी गिरकर 152958 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर पहुंचा। गोल्ड-गिनी फरवरी वायदा 1238 रुपये या 0.98 फीसदी गिरकर 124845 रुपये प्रति 8 ग्राम हुआ। गोल्ड-पेटल फरवरी वायदा 197 रुपये या 1.24 फीसदी गिरकर 15631 रुपये प्रति 1 ग्राम हुआ। सोना-मिनी मार्च वायदा सत्र के आरंभ में 151900 रुपये के भाव पर खूलकर, 152309 रुपये के दिन के उच्च और 149400 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 1853 रुपये या 1.21 फीसदी गिरकर 151024 रुपये प्रति 10 ग्राम हुआ। गोल्ड-टेन फरवरी वायदा प्रति 10 ग्राम सत्र के आरंभ में 154529 रुपये के भाव पर खूलकर, 154724 रुपये के दिन के उच्च और 152000 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 155220 रुपये के पिछले बंद के सामने 2082 रुपये या 1.34 फीसदी गिरकर 153138 रुपये प्रति 10 ग्राम हुआ।

चांदी के वायदाओं में चांदी मार्च वायदा सत्र के आरंभ में 235207 रुपये के भाव पर खूलकर, 237720 रुपये के दिन के उच्च और 229352 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 239891 रुपये के पिछले बंद के सामने 7453 रुपये या 3.11 फीसदी लुढ़ककर 232438 रुपये प्रति किलो बोला गया। इनके अलावा चांदी-मिनी फरवरी वायदा 7397 रुपये या 3.04 फीसदी गिरकर 235834 रुपये प्रति किलो हुआ। जबकि चांदी-माइक्रो फरवरी वायदा 7328 रुपये या 3.01 फीसदी घटकर 235924 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था।

▶▶ क्रूड ऑयल वायदा में 2 रुपये का नोमिनल सुधार : कमोडिटी वायदाओं में 27646.12 करोड़ रुपये और कमोडिटी ऑप्शंस में 228553.48 करोड़ रुपये का दर्ज हुआ टर्नओवर : सोना-चांदी के वायदाओं में 20618.94 करोड़ रुपये का हुआ कारोबार : बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स फ्यूचर्स 37388 पॉइंट के स्तर पर

मेटल वर्ग में 4731.62 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। तांबा फरवरी वायदा 31.05 रुपये या 2.59 फीसदी गिरकर 1167 रुपये प्रति किलो हुआ। जबकि जस्ता फरवरी वायदा 1.7 रुपये या 0.53 फीसदी गिरकर 319.45 रुपये प्रति किलो के भाव पर पहुंचा। इसके सामने एल्यूमीनियम फरवरी वायदा 95 पैसे या 0.31 फीसदी की नरमी के साथ 306.75 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि सीसा फरवरी वायदा 50 पैसे या 0.27 फीसदी टूटकर 187.45 रुपये प्रति किलो हुआ।

इन जिंसों के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में 2233.00 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स क्रूड ऑयल फरवरी वायदा सत्र के आरंभ में 5772 रुपये के भाव पर खूलकर, 5808 रुपये के दिन के उच्च और 5713 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 2 रुपये या 0.03 फीसदी की तेजी के संग 5793 रुपये प्रति बैरल हुआ। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी फरवरी वायदा 5 रुपये या 0.09 फीसदी की तेजी के संग 5795 रुपये प्रति बैरल के भाव पर पहुंचा। इनके अलावा नैचुरल गैस फरवरी वायदा 279.8 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 287 रुपये और नीचे में 274.2 रुपये पर पहुंचकर, 279.5 रुपये के पिछले बंद के सामने 6.8 रुपये या 2.43 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 286.3 रुपये प्रति एमएमबीटीयू पर आ गया। जबकि नैचुरल गैस-मिनी फरवरी वायदा 6.8 रुपये या 2.43 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 286.2 रुपये प्रति एमएमबीटीयू पर आ गया।

कृषि जिंसों में मेंथा ऑयल फरवरी वायदा 960.8 रुपये पर खूलकर, 40 पैसे या 0.04 फीसदी बढ़कर 960.5 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था।

कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर सोना के विभिन्न अनुबंधों में 11652.40 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 8966.54 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 4112.76 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 327.60 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 22.90 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 259.96 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। इन जिंसों के अलावा क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 842.14 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 1376.78 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। मेंथा ऑयल के वायदा में 1.87 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। जबकि कॉटन कैंडी के वायदाओं में 0.32 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

ओपन इंटरेस्ट सोना के वायदाओं में 8733 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 61872 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 33293 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 437715 लोट और गोल्ड-टेन के वायदाओं में 61344 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 8541 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 19712 लोट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 65304 लोट के स्तर पर था। क्रूड ऑयल के वायदाओं में 19984 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 21739 लोट के स्तर पर था।

इंडेक्स फ्यूचर्स में बुलडेक्स फरवरी वायदा 36900 पॉइंट पर खूलकर, 37599 के उच्च और 36900 के नीचले स्तर को छूकर, 575 पॉइंट घटकर 37388 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था।

कमोडिटी ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स में क्रूड ऑयल फरवरी 5800 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति बैरल 1 रुपये की गिरावट के साथ 59.8 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस फरवरी 280 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 4.85 रुपये की बढ़त के साथ 15.85 रुपये हुआ।

सोना फरवरी 160000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 445.5 रुपये की गिरावट के साथ 1022.5 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी फरवरी 240000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 3867.5 रुपये की गिरावट के साथ 7625 रुपये हुआ। तांबा फरवरी 1200 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 8.79 रुपये की गिरावट के साथ 10.2 रुपये हुआ। जस्ता फरवरी 320 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 4.71 रुपये की गिरावट के साथ 3.65 रुपये हुआ।

पुट ऑप्शंस में क्रूड ऑयल फरवरी 5700 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति बैरल 11.9 रुपये की गिरावट के साथ 16.8 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस फरवरी 280 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 2.6 रुपये की गिरावट के साथ 9.15 रुपये हुआ।

सोना फरवरी 150000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 120.5 रुपये की बढ़त के साथ 1980 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी फरवरी 200000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 379.5 रुपये की बढ़त के साथ 1897.5 रुपये हुआ। तांबा फरवरी 1100 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 1.73 रुपये की बढ़त के साथ 4.8 रुपये हुआ। जस्ता फरवरी 310 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 20 पैसे की नरमी के साथ 0.9 रुपये हुआ।